request the Government to prepare a fresh draft policy and it should be discussed first, and all options, all technological options should be considered while preparing it.

Demand to take measures to solve the problems being faced by Grameen Dak Sevak in the country

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभापति महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख आपकी अनुमति से कर रहा हूं जिसका विषय है - ग्रामीण डाक सेवकों को स्थायी करने के संबंध में।

महोदय, 35 लाख डाक सेवक ग्रामीण क्षेत्र में डाक सेवा का कार्य वर्षों से करते आ रहे हैं। यदि डाक सेवक ग्रामीण क्षेत्र की डाक सेवा से अपने आपको पृथक कर लें, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामवासियों को डाक नहीं मिल सकती। इतना महत्वपूर्ण कार्य करने वाले इन डाक सेवकों को न तो पेंशन और न ही ग्रेच्युटी की सुविधा मिल रही है। डाक विभाग को अनेकों बार उपरोक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन दिए गए, किन्तु केन्द्रीय डाक विभाग ने हल निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। स्थायीकरण की मांग पर भी डाक विभाग पूरी तरह से मौन है।

मेरा केन्द्रीय संचार मंत्री से अनुरोध है कि वे इन डाक सेवकों की समस्या का हल निकालने की दिशा में ठोस कार्य करें।

GOVERNMENT BILLS

The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals bill, 2005

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the prevention, control and eradication of infectious and contagious diseases affecting animals, for prevention of outbreak or spreading of such diseases from one State to another, and to meet the international obligations of India for facilitating import and export of animals and animal products and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

Sir, the proposed bill is intended to put in place a legislation to bring in a uniform code of law throughout the country to take care of disease outbreak in animals and for enabling an effective control and containment of infectious and contagious diseases in animals, including zoonotic diseases, to prevent their spread. The said Bill was first introduced in the Rajya Sabha in December, 2005 and was referred to the Parliamentary Standing Committee on Agriculture. After examination, the Committee suggested, in all 18 modifications. The provisions of the draft Bill have been suitably modified, wherever found necessary, taking into consideration the 10 modifications suggested of the Parliamentary Standing Committee.

The proposed Bill makes it obligatory on the part of the owner of the livestock which is suffering or suspected to be suffering from any disease to report the matter to the Village Officer or the Veterinary Officer. The provision is intended to ensure that the authorities concerned would come to know about the prevalence of any scheduled disease so as to enable them to take appropriate steps as authorized by law. To facilitate proper enforcement of the legislation, the Bill provides for the

appointment of officers and authorities to issue vaccination certificate, mandatory provisions to clean and disinfect vessels or vehicles carrying animals, power of entry and inspection for the concerned authorities, etc. The Bill also *See*ks to empower the concerned authorities to regulate movement of the diseased animals. Detailed penal provisions have also been incorporated to ensure effective and proper enforcement of various provisions.

The proposed legislation will strengthen the power of the State Governments to effectively tackle, control and eradicate the animal diseases. The Central legislation on the subject will bring in greater uniformity and co-ordination in this regard, apart from ensuring the prevention of spread of such diseases nation-wide. The provisions have been so conceived as to leave enough flexibility for taking into account the local conditions and the exigencies.

The question was proposed.

डा. नारायण सिंह मानकलाव (नाम निर्देशित): उपसभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय कृषि मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे पशुओं की इस बीमारी के संबंध में यह विधेयक लाए हैं। यह विधेयक 21 दिसंबर, 2005 को हाउस में प्रस्तुत हुआ और 9 जनवरी, 2006 को इसे स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया तथा 16 मई, 2007 को स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट दे दी। 16 मई, 2007 को स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद, अक्टूबर, 2008 में यह बिल कैबिनेट में पेश हुआ और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार इस बिल की लगभग 3 सालों की यात्रा है। इस दौरान देश ने बहुत ही संक्रामक रोगों से पीड़ित पशु और पक्षियों की हालत देखी है, bird flu से पूरा देश आलोड़ित हो गया था और आज भी पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में यह बीमारी व्याप्त है।

उपसभापति महोदय, मंत्री महोदय ने यह जो बिल रखा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि देर आयद दुरुस्त आयद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दो चीजें बहुत प्रमुख हैं - कृषि और पशुपालन। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है और इनके उत्पादों से साधारण कृषक, जो पशुपालक भी है, वह अपने जीविकोपार्जन का कार्य संचालित करता है। इस विधेयक में जानवरों के स्वास्थ्य के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की गई है और पशुओं में इस प्रकार के रोग, जो संक्रामक हो सकते हैं, जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकते हैं, उनकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए कारगर कदम उठाने का प्रयास किया गया है और वह प्रासंगिक भी है, क्योंकि आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पशु और पशु-उत्पादों का अगर हम आयात और निर्यात करना चाहते हैं, तो उसका स्वस्थ होना पहली आवश्यक शर्त है। इस संबंध में हमें यह भी पता चला है कि 1924 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत OIE का गठन किया गया, भारत भी जिसका सदस्य है। इस OIE के प्रमाणीकरण के बिना कोई भी देश, किसी भी पशु या पशु-उत्पाद का निर्यात नहीं कर सकता। इसके चलते यह obligatory हो गया था कि सरकार द्वारा एक अधिनियम बनाया जाए, जिसके चलते हम उनको रिपोर्ट कर सकें कि हमारे यहां कौन-कौन सी बीमारियां आईं और हम आवश्यकता पड़ने पर उनसे प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकें। इस विधेयक का महत्व और भी बढ़ जाता है, जब यह पता चलता है कि कुछ बीमारियां, कुछ संक्रामक रोग ऐसे भी हैं, जो मनुष्यों में भी संचरित हो सकते हैं। चूंकि मानव जीवन भी पशुओं से जुड़ा हुआ जीवन है, अतः उसके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए इसलिए इस बिल की महत्ता और भी बढ़ जाती है। मनुष्य और पशुओं का साथ आदि काल से है, पशु असहाय है, निरीह है, अबोल है, मनुष्य के अधीन है, मानव के संरक्षण से ही उसका जीवन चलता है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें पशुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। दूध, मांस, अंडे और अन्य प्रकार की सेवाएं पशु के जरिए ही मनुष्य आदि काल से लेता आया है। इसका संरक्षण होने के नाते पशुधन की सुरक्षा और संरक्षण मानव समाज का धर्म है। संभवतः इसी धर्म से प्रेरित

होकर सरकार ने यह विधेयक पेश किया है। श्रीमान्, इस विधेयक में कुछ मूल तत्व हैं। उसमें पहला है पशु, फिर भी पशु की बीमारी, पशु पालक, निवारण और उसके विभिन्न आयामों पर इस में चर्चा की गई है। अब मैं इस बिल के मूल पाठ पर आता हूं और बिन्दुवार या खंडवार इसकी विवेचना करना चाहता हूं। श्रीमान्, परिभाषा के खंड 2(क) में लिखा है :

"पशु" से अभिप्रेत है :

(1) ढोर, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन;

(2) कुत्ता, बिल्ली, सुअर, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, कुक्कुट, मधुमक्खी

श्रीमान्, मेरा मानना यह है कि ढोर शब्द अस्पष्ट है और इसमें गाय का कहीं उल्लेख नहीं है। निश्तिर तौर से गाय भी एक पशु है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखण्ड): गांव की भाषा में ढोर और डग्गर कहते हैं न!

डा. नारायण सिंह मानकलाव: ऐसे तो सारे जानवरों को ही ढोर कहते हैं। तुलसी दास जी का ढोर से संबंधित एक बहुत famous पंक्ति है, पर मैं इस पर आगे कुछ नहीं कहता हूं, चूंकि यहां कई लोग बैठे हैं। इस तरह से तुलसी दास जी भी विवेचना के विषय बन जाएंगे और आलोचना के पात्र बन जाएंगे, परंतु उसमें उन्होंने ढोर शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें उनका आशय सिद्ध रूप से पशुओं के लिए है। यहां पर ढोर के बाद पूरी पशु जाति का उल्लेख है, फिर भी ढोर को अलग लिखा है और भैंस, बकरी, याक और मिथुन भी लिखा है, परंतु इसमें गाय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैं यही आगे कहना चाहता हूं कि रोगों की जो अनुसूचित सूची दी गई है, उसमें हर जानवर की हर जाति का उल्लेख है कि भैंस में यह बीमारी होगी, बकरी में यह बीमारी होगी, भेड़ में यह बीमारी होगी, सुअर में यह बीमारी होगी, मधुमक्खी में यह बीमारी होगी, परंतु उसमें भी गाय का कहीं उल्लेख नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस ढोर शब्द में गाय आती है, और यदि आती है तो ढोर शब्द के साथ bracket में गाय लिखें ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि गाय के बारे में हमारी क्या मान्यता है, हमारी क्या सोच है। अब श्रीमान्, **...(व्यवधान)...।**

SHRI JABIR HUSAIN (Bihar): Sir, can we discuss about those pepole who are not present in the House?

डा. नारायण सिंह मानकलाव: महोदय, माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं **...(व्यवधान)...।**

श्री उपसभापति: नहीं, वे कुछ नहीं बोल रहे हैं **...(व्यवधान)...।** गाय हाउस में नहीं है **...(व्यवधान)...** उस पर डिसकस करते **...(व्यवधान)...।**

डा. नारायण सिंह मानकलाव: महोदय, यह बात सही है **...(व्यवधान)...।**

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, यह बात सही है कि हाउस में उसके बारे में डिसकस कर सकते हैं, but we are law makers, we are making law for them.

डा. नारायण सिंह मानकलाव: महोदय, गाय निरीहता का सबूत है और हममें से भी कई उस श्रेणी में आ सकते हैं, इसलिए हमारी उपस्थिति और गाय की उपस्थिति, दोनों को ही मान कर चलते हैं। श्रीमान्, अब मैं इस बिल की खंडवार विवेचना करना चाहता हूं। इस बिल के खंड 4 (1) और (2) में सूचना देने वाले के पास रोग से संक्रांत होने का विश्वास होने का कारण होना चाहिए। यह एक टर्म है कि जो भी सूचना देगा कि मेरा जानवर बीमार है, तो

उसके पास रोग से संक्रांत होने का विश्वास होने का कारण होना चाहिए। यह कारण दो तरह से हो सकता है, एक तो पशु के रोग के लक्षण से भी मालूम पड़ सकता है कि पशु में यह रोग है, जिसको symptoms कहते हैं। अगर जानवर में वे symptoms उभरते हैं, तो यह पता चल सकता है कि जानवर में यह रोग है। दूसरा तरीका है कि प्रयोगशाला में जांच के बाद यह पता चलना कि इस जानवर में यह रोग है। पशु में व्याप्त रोग के लक्षण के आधार पर कोई भी veterinary doctor यह मानने को तैयार नहीं है कि यह इस रोग से पीड़ित है।

श्री उपसभापति: आप लंच के बाद कंटीन्यू करें।

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at one minute past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

The prevention and Control of Infections and Contagious Diseases in Animals Bill, 2005 - *Contd.*

माननीय उपसभापति महोदय, मैं रोग की सूचना देने वाले के पास उसके विश्वास करने के कारण के बारे में बता रहा था और उसके लिए रोग के लक्षण इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी लैबोरेटरी की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि veterinary की लेबोरेटरीज देश में किस अनुपात में हैं और उनसे रिपोर्ट का पोजिटिव और नेगेटिव आना काफी मुश्किल मामला है। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मेरे स्वयं के साथ घटित एक आप बीती घटना आपको सुनाना चाहता हूं जिससे सारी स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाएगा। पिछले माह घोड़ों में एक equine influenza नामक बीमारी का प्रादुर्भाव हुआ। भारत सरकार ने संबंधित राज्यों को इसकी सूचना दी और घोड़ों की आवाजाही को रोकने का आग्रह किया। उसके उपरांत भी घोड़ों का आना-जाना जारी रहा। महोदय, राजस्थान के पुष्कर शहर में भारत का बहुत प्रसिद्ध पशु मेला लगता है - उसका आयोजन हुआ। मुझे सूचना नहीं थी इसलिए मैं भी अपने घोड़े लेकर उस मेले में गया। वहां पर दूसरे और तीसरे दिन ही मेरे घोड़े और अन्य सारे घोड़े equine influenza से ग्रसित हो गए। घोड़ों की हालत बिगड़ने लगी। पशु-पालक परेशान हो गए। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बैठने का अवसर प्राप्त करता हूं और पशु पालकों ने मुझे कहा और मैं वहां के अधिकारियों से मिला। ज्वाइंट डायरेक्टर ने मुझे कहा कि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि यह equine influenza है। मैंने कहा कि ये सारे लक्षण जो आप बताते हैं, जो इंटरनेट से लिए हैं और जो veterinary doctors कहते हैं, वे सारे लक्षण इन घोड़ों में हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते, हम इसका ब्लड सैंपल लेंगे। और ब्लड सैंपल लेने के बाद पॉजिटिव आने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा कि आप ब्लड सैंपल ले लीजिए। 11 नवम्बर को ब्लड सैंपल लिया गया और मुझे कहा गया कि यह ब्लड सैंपल पहले जयपुर जाएगा और फिर हिन्दुस्तान में हिसार में एक ही जगह है एन.आर.ई.सी., जहां पर घोड़ों के खून की जांच होगी और वह लेबोरेटरी यह कहेगी कि यह घोड़ा इंफ्ल्युंजा से प्रभावित है या नहीं। इसमें 14 दिन लगेंगे तथा 14 दिन बाद में उसकी सैकंड रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के आने के बाद फिर उसका सैकंड सैंपल लेंगे और उसके बाद ही यह कंफर्म होगा कि यह इंफ्ल्युंजा है या नहीं। मैंने सैंपल दिलवाये और आवश्यक ट्रीटमेंट किया और घोड़े घर आ गए। जब 14 दिन बाद अधिकारियों से सम्पर्क किया गया तो पता चला कि वह सैंपल जयपुर में ही पड़ा हुआ है और हिसार गया ही नहीं। तब मेरे हल्ला करने पर वह सैंपल उसी दिन 24 तारीख को 15 दिन बाद वह हिसार गया और उसके बाद फिर दूसरा सैंपल दिया गया। मुझे आज भी पता नहीं है कि मेरे घोड़ों को क्या बीमारी थी। लेकिन वे ट्रीटमेंट से ठीक हो गए। अगर ऐसा मेरे साथ हो सकता है तो एक साधारण पशु पालक की क्या स्थिति होती होगी, जो कि न कुछ वह जानता है और न जोइंट डायरेक्टर से बात ही कर सकता है और न डाक्टर के सामने ही जा

सकता है। इस तरह से दूरदराज में रहने वाले उस पशु पालक की हालत क्या हो सकती है। आपने केवल उसको इस बात को कह दिया उसको विश्वास करने का कारण होना चाहिए। इसलिए मैं इस घटना के माध्यम से आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें किसी पशु पालक को, अश्व पालक को या किसी पालक को कोई लाभ होने वाला नहीं है और वह इसी उधेड़बुन में घूमता फिरता रहेगा कि मेरे घोड़े को क्या हुआ, मेरे जानवर को क्या हुआ और तब तक या तो जानवर कालकवलित हो जाएगा या बीमार होकर के फिर ठीक हो जाएगा। स्टेंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पेज-60 पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनको मैं कोट करना चाहता हूं।

"समिति का विचार है कि केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने और पशुओं में होने वाली बीमारियों की तत्काल पहचान करने के लिए ऐसी जांच और अनुसंधान प्रयोगशालाएं खोलने में मदद करनी चाहिए, जो किसानों के लिए सुगम हो। भारत सरकार को जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को निधि भी मुहैया करानी चाहिए और ऐसी प्रत्येक जांच प्रयोगशाला क्षेत्र विशेष की पशु संख्या के आधार पर दस और पंद्रह गांवों के लिए स्थापित की जानी चाहिए। इन प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों को पशु चिकित्सा विद्यालय में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।"

इसके बदले में मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप दस-पांच को छोड़िए, ब्लॉक स्तर पर भी आप एक ऐसी लेबोरेट्री स्थापित कर दीजिए जिससे लोग लाभांवित हो सकें और पता लगा सकें कि उनके जानवर वास्तव में संक्रमित हैं या नहीं।

श्रीमान, आगे खण्ड-5 और 2 में संक्रमित पशुओं के अलग रखने का दायित्व पशु स्वामियों पर डाला है। अगर किसी का एक पशु संक्रमित हो गया है तो उसको इस बिल के अनुसार यह आदेश दिया गया है कि वह अपने पशु को अलग रखेगा, यह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य तो है, परन्तु आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस आदमी के पास एक, दो या तीन पशु हैं या चार पशु हैं और छोटे से बाड़े में, छोटी परिधि में वह अपने पशुओं को बांधता है, तो वह किस प्रकार अपने एक जानवर को अलग ले जाकर कहां रखेगा, कैसे रखेगा। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि इसको पशु स्वामी अलग न रखकर, आपने जो खण्ड-5 के सैक्शन-3 में प्रावधान किया है, जिसमें आपने लिखा है कि ग्राम पंचायत, नगरपालिका या स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर अलग रखने की व्यवस्था करें। इसका अर्थ यह है कि पशु पालक को ज्यों ही मालूम पड़ जाए कि उसका पशु संक्रमित हो गया है, तो इसकी ग्राम पंचायत सामूहिक व्यवस्था कर सकती है, क्योंकि जब यह रोग फैलता है तो एपेडेमिक रूप में फैलता है, कई पशु एक साथ होते हैं, तो उस क्षेत्र विशेष की ग्राम पंचायत या नगर पालिका एक बाड़ा या एक स्थान लेकर के उन सारे गरीब पशु पालकों के जानवरों को एक जगह एकत्रित कर सकते हैं और उनका रख-रखाव, देखभाल और उनका निपटारा करने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए यह जो पहले प्रॉविजन है कि पशु-पालक ही इसकी देखरेख करेंगे, यह जो बाध्यता है, यह खत्म होनी चाहिए और इसको ग्राम पंचायत के आधार पर करना चाहिए। खण्ड 6 उपभाग 3 और 4 में राज्य सरकार द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र में संक्रामक पशु जाति के और सभी पशुओं को अनिवार्य रूप से टीका लगाया जाएगा, यह टीका राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी, ऐसा प्रावधान है। मेरा यह मानना है कि यह जो टीका है, अलग-अलग बीमारियों में अलग-अलग टीके होते हैं और यह जो टीके की बात है, जहां तक मेरी जानकारी है जब equine influenza की बात चली, जो पता किया गया कि टीका कहां मिलेगा, क्योंकि मेरे जो अन्य घोड़े थे, उनको मुझे सुरक्षित करना था और गांव के जो अन्य लोगों के घोड़े थे, उनको सुरक्षित करना था, तो पता चला कि यह टीका बाहर से, विदेश से आएगा, यहां पर नहीं है।

श्री उपसभापति: आपको बोलते हुए बीस मिनट का समय हो चुका है और टोटल आपकी पार्टी का 26 मिनट का समय है। अभी एक वक्ता और आपकी पार्टी से बोलने वाले हैं। ...**(व्यवधान)**...

डा. नारायण सिंह मानकलाव: सर, अभी खत्म कर देते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: It is a very important Bill, especially keeping in mine the rural masses, इस पर बोलने वाले भी कम हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: इस पर बोलने वाले सदस्य हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री एस.एस. अहलुवालिया: जो भी हैं, ये चूंकि पशु-पालक हैं और जो चीजें वे सदन के सामने रख रहे हैं, वह शरद पवार जी को इसके बारे में बता रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, मैं इशारा दे रहा हूं कि अभी एक और सदस्य बोलने वाले हैं।

डा. नारायण सिंह मानकलाव: सर, मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा। सर, मैं कह रहा था कि टीके की जो बात है, टीके की उपलब्धता पर मुझे संदेह है। equine influenza के टीके की कमी की बात मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया कि वह हिन्दुस्तान में उपलब्ध नहीं है। अब कितनी बीमारियों के कितने टीके ऐसे हैं, जो यहां उपलब्ध हैं या नहीं हैं, अगर उपलब्ध हैं, तो किस मात्रा में है, ऐपिडेमिक की स्थिति में वे कहां तक उपलब्ध होंगे, क्योंकि अगर बीमारी नहीं है, तो उन टीको को प्रोडक्ट करने का कोई फायदा नहीं है और बीमारी फैलने में उनको प्रोडक्ट करने में जितना टाइम लगता है, उस समय तक बीमारी फैल जाती है। ये सारी चीजें देखने की हैं क्योंकि इनको नहीं देखा गया, तो ऐसा लगेगा कि टीके की जो अनिवार्यता आपने की है, वह अनिवार्यता है ही नहीं, तो किसको लगाया जाएगा और कौन लगाएगा?

सर, इस विधेयक में यह चीज पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती है और व्यावहारिक दृष्टि से इसको मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विधेयक के साथ विभिन्न पशुओं की जातियों के विभिन्न रोगों के लिए टीकों की उपलब्धता संदिग्ध हैं। उक्त संक्रामक रोगों में कई रोगों के लिए टीके विदेश से आयात करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में, साधारण और गरीब पशु-पालक के लिए उन्हें खरीद कर लगाने की अनिवार्यता अव्यावहारिक लगती है। हां, इस खण्ड के 6(4) में यह बाध्य होना चाहिए था कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार आवश्यक टीके निशुल्क उपलब्ध करवाए। क्योंकि टीकों की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि एक साधारण पशु-पालक इनको नहीं लगवा सकता है। सरकार की तरफ से पशु-पालकों को निशुल्क टीके उपलब्ध करवाए जाने चाहिए क्योंकि यह बीमारी बार-बार नहीं होती है और जब कभी कोई बीमारी होती है, तो उसके लिए निशुल्क टीकों की व्यवस्था होनी चाहिए। यथासमय टीके उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जब बीमारी के बारे में पहले से पता चल जाए कि बीमारी फैल रही है, तो तत्काल उन्हें टीके की व्यवस्था करनी चाहिए और अगर वे टीके की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

इसी में लिखा हुआ है कि चिन्हित करेगा एक डाक्टर पूरे तहसील में, सब डिवीजन में एक डाक्टर है, वह पूरे जानवरों को चिन्हित करेगा, उसके बाद में उसमें मार्किंग करेगा, टीका लगाएगा, यह सब ऐसा लगता है कि कहीं अच्छे से एयरकंडीशन में बैठकर सारी लिखा-पढ़ी की गई है, व्यावहारिक स्थिति में ऐसा संभव नहीं है। जो डाक्टर्स की संख्या फील्ड में उपलब्ध है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि ये सारी चीजें हो पाएंगी, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर्स की ज्यादा संख्या चाहिए। हमारे यहां तो साधारण बीमारियों के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो यह कैसे संभव हो सकेगा।

खण्ड 14 और 15 में चैकपोस्ट और करन्तीन कैंपों के बारे में विवेचना है, यह बहुत अच्छी बात है। इससे काफी फर्क पड़ेगा। परन्तु इसमें एक जगह पर लिखा है कि आवागमन पर चैकपोस्ट निगरानी रखेंगे, इसका मुझे संदेह है कि इसका दुरूपयोग हो सकता है। असंक्रामक और स्वस्थ पशुओं के आवागमन पर भी चैक पोस्ट वाले बैठ जाएंगे और उनसे वसूली करेंगे और कहेंगे कि आप अपना जानवर लेकर जा रहे हो। आज भी यह कभी-कभी हो जाता है, तो हमें इसके लिए भी विचार करना पड़ेगा कि चैक पोस्ट पर होने वाले दुष्परिणामों से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। खंड-23 में संक्रांत पशुओं को अलग रखे जाने तथा परीक्षण चिकित्सा का प्रावधान है। पशु

पालक के लिए तो पशु अलग रखने की बात न व्यवहारिक है और उसके लिए परीक्षण चिकित्सा की बात मायने रखती है। श्रीमन् आज भी लाखों पशुओं का इलाज डॉक्टर नहीं करते हैं, बल्कि पारंपरिक नुस्खों और घरेलू तरीकों से लाखों पशुओं का इलाज गांवों में करते हैं। अगर कोई यह मानता है कि साधारण बीमारियों का इलाज भी जानवरों के डॉक्टर करते हैं, तो यह भ्रांति है। सच्चाई यह है कि जो अपने घर के साधन हैं और जो पुराने नुस्खे हैं, हम उनसे जानवरों का इलाज करते हैं। इस परिस्थिति में जब सैकड़ों की तादाद में जानवर संक्रमित हो जाते हैं, तो यह व्यवस्था चलने वाली नहीं है। इसी प्रसंग में कृषि मंत्रालय की स्टेंडिंग कमेटी ने इस विधयेक पर चर्चा कर अपने 21वें प्रतिवेदन के पेज संख्या-6 पर जो लिखा है, वह प्रासंगिक है। मैं उसको समय के अभाव में कोट नहीं करना चाहता, परन्तु आप यह याद रखें कि प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, आवश्यक सूची सक्षम होनी चाहिए और पशु संख्या के आधार पर स्थापना होनी चाहिए। यह सब तो इसमें आ गया है, श्रीमन् खंड-25 बहुत ही महत्वपूर्ण है, संक्रामक पशु को सहज मृत्यु की युक्ति। जो संक्रामक पशु हैं, उनकी सहज मृत्यु, कष्ट रहित मृत्यु का इसमें प्रावधान किया गया है। आदमी को कष्ट रहित मृत्यु के लिए शायद खुद यह लिखकर देना पड़ता है कि मैं मृत्यु चाहता हूं, लेकिन जानवर तो यह नहीं कह सकता है कि मुझे कष्ट रहित मृत्यु चाहिए। यह तो तय करेगा डॉक्टर, यह तो तय करेगा पशुपालक या पशु का स्वामी और विशेषतौर से तो डॉक्टर ही तय करेगा। मेरा यह निवदेन है कि जो अपने सभी 40-50 बीमारियों के नाम लिखे हैं, उन सब बीमारियों में ज्यादातर ऐसी बीमारियां हैं, जो दस-पन्द्रह दिन में ठीक हो जाती हैं। इससे पशु के शरीर में हानि होती है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है। यदि सैकंड्री इंफेक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए, तो वह बीमारी ठीक हो जाती है। जानलेवा बीमारी को अलग से सूचीबद्ध करना चाहिए। जब ये जानलेवा बीमारियां अलग से सूचीबद्ध हो जाएंगी तो तब डॉक्टर के पास यह विकल्प ही नहीं बचेगा कि इसका क्या करना है। अभी हम डॉक्टर पर निर्भर करेंगे कि वह किसको मृत्यु देता है और किसको मृत्यु नहीं देता है। यह सौ साल पुराना कानून है। आज पचास-साठ साल पहले टीबी के मरीज को कहते थे कि यह मरेगा, लेकिन आज एंटी बॉयटिक बन गए हैं और अन्य इलाज भी आ गए हैं। इसलिए इसके चलते इस सूची का भी निर्माण करना चाहिए, जिसमें जानलेवा बीमारियों की सहज मृत्यु की कल्पना हो। महोदय, मैं सहज मृत्यु के संदर्भ में ही आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक काश्तकार, एक पशुपालक अपने पशुओं के आधार पर ही अपना जीवनयापन करता है। उसकी जीविका का आधार पशु है। अगर उसकी सहज मृत्यु की रेकमेंडेशन हो गई, तो उसका हर्जाना वह सहन नहीं कर पाएगा और कृषकों की आत्महत्याओं के साथ-साथ पशुपालक भी आत्महत्या की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए मेरा आप से यह अनुग्रह है कि सरकार का हाथ, गरीब के साथ जो नारा है, तो पशुपालक से ज्यादा गरीब कोई नहीं है। उसको उस मरे हुए पशु या जिसको मृत्यु प्राप्त हो, उस पशु का मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी अनुशंसा आपके विभाग की स्थाई समिति ने भी की है और मैं भी आप से पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करूंगा, क्योंकि उसके बिना उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। ...**(समय की घंटी)**... जिस पशु के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है, यदि उस पशु को ऐसी बीमारी हो गई, तो निश्चित तौर से उसको आत्महत्या करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए कोई और विकल्प हीं नहीं बचता है। इसलिए आप उसके मुआवजे के बारे में कुछ न कुछ सोंचे या इंश्योरेंस के बारे में सोचें, ऐसा स्टेंडिंग कमेटी ने सजेस्ट किया है। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि सभी जातियों के पशु किसी-न-किसी आदमी के स्वामित्व और संरक्षण में हैं, क्योंकि इनकी उपादेयता और उपयोगिता है। परन्तु खेद है कि गोपाल के देश में गाय एक ऐसा पशु है, जो बहुतायत संख्या में बिना स्वामी के विचरण कर रही है। हमारी अपनी नीतियों के कारण आज गाय निस्सहाय और असहाय जानवर बन गई है और दूसरा है Street Dogs. इन दो जानवरों में व्याप्त बीमारी से बीमार पशुओं का अधिग्रहण करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, लोकल प्रशासन को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई मालिक नहीं है। अगर मालिक नहीं होने के कारण वे इलाज से वंचित रह गए, टीकों से वंचित रह गए, उनके

अधिग्रहण करने से वंचित रह गए, तो वे समाज में बीमारी फैला देंगे और उससे मनुष्यों में भी यह रोग बढ़ सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा करने के लिए आप इसको सरकारी या लोकल प्रशासन के तहत ही लगवाएं। ...**(समय की घंटी)**...

एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम पशुओं का आयात करते हैं। नस्ल सुधार के लिए हमने वर्षों से पशुओं का आयात किया है। अभी भी हम सीमने बाहर से मंगाते हैं, पशु भी बाहस से आते हैं। इस पूरे बिल में उन जानवरों के लिए, उन उत्पादों के लिए, जो हमारे देश में आते हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि इसके लिए अलग से कोई कानून हो, परन्तु इसमें ऐसी व्यवस्था होती, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संक्रमित चीज या पशु हमारे यहां नहीं आ सकते।

जहां तक निर्यात का प्रश्न है, निश्चित तौर से हमारे किसी जानवर की बाहर कोई मांग नहीं है, सिवाय मांस के। एक मांग, जो पिछले कई वर्षों से उठ रही है, आप भी जानते हैं, वह है indigenous horse, मारवाड़ी हॉर्स की। उसको बाहर लोग मांगते हैं, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं भेज सकते कि उसमें एक बीमारी का stigma लगा हुआ है। उसके चलते हमें घोड़ों को श्रीलंका और मलेशिया के माध्यम से यूरोप भेजना पड़ता है, जबकि यूरोप के कई देशों में वह बीमारी व्याप्त है, जिस बीमारी के नाम से हमको रोका जाता है। फिर भी हमको इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है।

स्थाई समिति ने आपको कई चीजें बताई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आईसीएआर की लाइन पर आप यहां एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलें, जो निश्चित तौर से इसके पूरे मसले को, रिसर्च को और सारी चीजों को regulate करे।

श्रीमान्, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कानून बनते हैं, दस्तावेज के रूप में लाइब्रेरी की अलमारी में शोभा देने के रूप में नहीं बनें, उनके व्यावहारिक पक्ष को देखा जाए। उनको क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास क्या infrastructure है? क्या हमारे डाक्टर्स, क्या हमारी लेबोरेटरीज, क्या हमारे हॉस्पिटल्स दूर-दराज के पशुपालक तक पहुंच कर इसका क्रियान्वयन कर सकेंगे? अगर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। infrastructure का creation करना पड़ेगा और वे सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, जिनसे इस कानून, एक बहुत अच्छा कानून बना है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सके और पशुओं को इन रोगों से, इन संक्रमित रोगों से मुक्त किया जा सके और मानव जीवन को भी सुरक्षित किया जा सके। धन्यवाद।

SHRI JESUDASU SEELAM (ANDHRA PRADESH): Mr. Deputy Chairman, Sir, I stand to support the Prevention and Control of infectious and Contagious Diseases in Animals Bill, 2005. I would like to congratulate and compliment the hon. Minister for bringing forward this Bill. As pointed out by my senior colleague, it is important that this Bill is considered and passed unanimously. As you are aware, this Bill has not been brought just now, but it was brought when the Government took over in 2005. Then, it was referred to the Standing Committee and the Standing Committee went into various clauses and they made certain suggestions. Those suggestions were again examined by the Ministry and most of the suggestions were incorporated and acted upon, but some of the suggestions, which were basically administrative in nature, were taken care by administrative actions, and accordingly, the Bill has been now placed before the House. I would like to draw the attention of the Members of the House that basically, the Bill is brought to prevent, contain, control and stop the spread of certain contagious and infectious disease among animals. Secondly, the outbreak or spread of such diseases from one State to another, and, thirdly, to meet the international

obligations. Under article 253 of Constitution of India, the Parliament is empowered to make certain laws which enable us to conform to the international Agreements and, also, to make treaties with other countries.

Sir, both, Dr. Narayan Singh Manaklao and I, had the opportunity to work in the Animal Welfare Board for quite some time. I would like to submit that the animals are part of the human culture. God created this universe, and, alongwith human beings, He also created animals. Animals have every right to be treated properly; they have every right to be taken care of. I think, they are intertwined in our social, economic and religious lives. They are treated with veneration; they are treated with great respect. Sir, you know that we have symbols of animals as our national symbols. We treat them with great respect. They are also linked to our lives because India is basically an agrarian country where most of the rural folk depend on them in their agricultural operations, which include the draught animals. Of course, the role of the draught animals is decreasing as we are progressing technologically.

But, still we depend largely on it for our food, meat, wheat products and its by-products. We consume a lot of meat, and, not only, we consume it here in our country, but we also export animals and animal products. Fortunately, Sir, we are number one in the entire world in the cattle and buffalo population, and, we are number two in sheep and goat population. We have one-sixth of the world's cattle population and nearly half of the world's buffalo population.

We feel proud in abundant flora and fauna and the animal population is also really making us proud. We export animals to Europe, Arab countries, Bangladesh, Pakistan and also to our neighbours also. Last year, we earned around Rs. 3,000 crores by exporting meat. We are also number two in poultry exports. We know that the Government of India is promoting egg-consumption by asking people to take one egg everyday. Sir, because these animals are intertwined in our lives, it is our duty to take care of their health.

Of course, the Government of India, starting from the Second Five Year Plan, has been implementing various programmes to control the diseases amongst the animals. Moreover, it is also assisting various State Governments in implementing plans and programmes. Where the Government of India is not doing it directly, they do it through the State Governments. Various State Governments take up different programmes at the District level. We have field-level officers and there are committed veterinary doctors who help people in the villages to diagnose as to what is wrong with their pet, draught animal or whatever it is. There are some people who love animals much more than they love their siblings. I think, this is a great affinity between the animals and the human beings, especially in India. Sir, in this background, this Bill indirectly provides for right of an animal to be taken to clinic. Suppose anybody notices that a particular animal is suffering, he is bound to take that animal to a clinic. These are certain provisions in the Bill.

I would like to say that more than social and cultural links, this Bill is basically brought to help us to facilitate our international treaty and also to bring a uniform law throughout the country in respect of controlling and preventing such communicable and contagious diseases. When you say that we are exporting on a huge scale, I must also tell you, we also have to abide by certain international

obligations. International Animal Health Organisation, which used to be called OIE, is an organisation which basically determines the guidelines for status of health of a particular animal for export. India is also a member of this Organisation. We keep on getting certificates. Sir, we have certain specific areas. For instance, the Murrah buffalo of Haryana is famous worldwide. We have the bull of Ongole. Ongole bulls are worldwide famous. They are from Andhra Pradesh. We have great culture of specific breed which is of world standards. I think, once we have to export such animals, we need to get clearance from this Organisation which specifies certain guidelines which are determined as a part of international animal health code. So, in this connection, this Bill is brought under article 253 which empowers this House to enact such a law.

Sir, this legislation will provide for monitoring, effective control and containment of infectious and contagious diseases which normally inflict the animals. As I said before, certain areas should be declared as controlled areas. Controlled areas means such areas take all the sick animals and then provide for declaration of that area as a controlled area. This also provides for elimination and probably control of spread of such disease. We have disease like Anthrax which is a deadly disease. Nowadays, Bird Flu is also noticed everywhere. Foot and mouth is also a very common disease. This Bill also lists out all these diseases. I do not want to repeat these diseases which are not only infectious but also contagious and harmful for the human beings, harmful from the social harmony point of view. Rabies and Anthrax are fast increasing. As you are aware, as far as disease control among human beings is concerned, we are able to enhance our technological advancement and then are able to find cure for all the ailments. Similarly, we should be able to treat the menace of certain contagious diseases which could be harmful for human beings. That is why this Bill will provide for regulatory mechanism. Among other things, Sir, if you notice, this Bill has seven chapters and 45 clauses dealing with various provisions for control of these scheduled disease which are listed animal-wise and bird-wise. Certain category of animals have these diseases like foot and mouth disease, a common disease which we used to have for a long time. We have been able to now contain it. Similarly, in that, there are sub-virus, virus O, virus A, virus C, virus Asia one and virus which was not stereotype. Like that, animals get infected because of probably immunity also. So, it is important that we notice them and treat these diseases at a right time and then administer these drugs. So, is the case with vaccination. How to use this vaccination. Then the certification also. Sir, we have seen in recent years that because of the absence of such a uniform law throughout the States, different people are adopting different procedures, leading to complications and some misuse of certain procedures leading to litigation. We have also seen a lot of write-ups in the paper regarding some of the NGOs because we must appreciate that in this country, a lot of NGOs are working hard. They are taking care of the sick animals. They are treating them and they also need to know that this particular section exists. It should be controlled, properly regulated and guided so that animals are protected, taken care of and contagious and infectious diseases are prevented from spreading from one State to the other. I think these provisions are well laid. I only hope that this Bill is passed unanimously and the machinery is put in place as quickly as possible because it is already delayed. For the last 3 years, the Standing Committee is seized of this matter and it took some time to clear it. I suppose the Standing Committee made certain observations. I wish the hon. Minister

would keep those points in mind while implementing because the Standing Committee felt that there is a need to have a separate designated officer instead of leaving it to the village officer because village officers do have a lot of other work and designating them as specified officers may be a problem. I think we should take it up seriously that there should be a separate cell to administer the provisions of this Bill which will become an Act after its passage. With these words, I once again compliment and congratulate the hon. Minister for bringing such a piece of wonderful legislation which is going to take care of the problems associated with our animals who are part of our social, economic and cultural life. Thank you very much.

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Thank you, Sir. I rise to support this Bill. It is an undeniable fact that livestock is an asset of our country like other assets. So, we must take care of this asset, and I firmly believe that it is our national duty to protect this asset. Animals are a part of our civilization. It is a fact that civilization is built by man. But in our country, there is a good scope and a good place for different type of animals who are very much lovable to us. In this perspective, I would like to welcome this comprehensive Bill which is thought out. Apart from this, it is also a fact that our country is agriculture-based, and till date, agricultural production and agricultural activities depend upon animals. So, it is our bounden duty to take care of livestock of different types of animals.

Sir, my second point is this. I have found that there are a lot of chapters in the Bill; seven or eight chapters. There are many schemes run by the Centre concerning the animal disease. They give assistance to the States for preventing this disease, which is infectious. There is a national project. I am referring to the NPRE. Another project is FMD-CP, Foot Mouth Diseases Control Programme. I have seen that there are some districts included in this national scheme; 54 districts. My suggestion or my proposal is that the number of these districts should be enhanced. Sir, many times, it has come to our notice – I have seen this in the newspapers also – that the animals are affected by this type of diseases, Foot Mouth Disease etc. So, there is an ample scope for enhancing the number of districts. All these are the Central Programmes. But all the Central Programmes are implemented by the States. So, there is a scope for supervision. If there is no supervision, all the schemes will become void. So, I would request the hon. Minister to find out a specific mechanism for supervising the schemes properly. I have noticed that some guidelines are there. But that is not enough.

Proper and timely funding of the project is another part. The Government should respond timely by allocating funds to the States for all these programmes which originate from the Government of India.

Sir, my fourth point is this. I am very much worried about it, and I want to specifically mention here that West Bengal is a Bird Flu-hit State. Six or seven months back or, say, nearly one year back, several districts were hit by the Bird Flu. Till today, only one or two districts are affected by this, and one of them – perhaps the Minister knows this – is Malda. Malda is badly affected by it; we are very much worried about it. Sir, my submission is like this. The poultry owners are not affected, but domestically, every house owner, every common dweller is affected by the Bird Flu. Sir, my submission is, there is a scope for compensation. The modalities for paying compensation have to be properly found out. The modalities should be introduced by the Central Government in

consultation with the State Governments. My demand is that the entire expenditure should be borne by the Exchequer of the Government of India. There is an important word so far as Bird Flu is concerned. It is, called 'culling'. It is a very dangerous thing. It is very difficult to cull or segregate the affected animals because these birds may belong to a widow or a self-employed woman. And if there are only three or four birds, then, it is very difficult to cull. So, we must find a way out. Many times, it is inhuman also at many places. So, we must find out a proper mechanism for culling these affected birds. We must seek the help of self-help groups in villages. Basically, it is the tradition of India that birds and goats are very much affectionate towards the common people.

Another point is that when the officers go to cull the animals, they must take tablet like Tamiflu. It is a very costly tablet and it must be adequately supplied by the Government of India. I demand that there should not be any improper supply, so far as proper medicines are concerned because those who cull or segregate the animals are going to be in danger today or tomorrow. So, it is our duty to equip them properly to face this problem.

Another point regarding this bird flu, which was mentioned by the first speaker also, is how you detect the bird flu. There is only one laboratory in Bhopal. Why don't you have three or four laboratories in different metro cities of the country? If more laboratories are established in different cities, it will be helpful. Then, who will give the certificate that there is bird flu or other diseases? There should be a designated officer in the municipality or in the local panchayat area. It is not clearly stated in the Bill. It was one of the suggestions of the Standing Committee when it was discussed.

Another point is that one of the diseases mentioned in the Bill is anthrax. West Bengal is also an anthrax-affected State. I belong to Murshidabad district. Three or four times I came to know that the cows in the district were affected by the anthrax disease. People use the meat of these cows and feel unwell. It is a very serious situation. I have a news report that three or four people died after taking anthrax-affected cow meat.

I would like to say again one thing, so far as the Bill is concerned. How do we work when there is infection and there is no immunity? The immune mechanism should be strong. It is stated in the Bill that it will be properly monitored. It will protect life if we properly look into it. I would like to get a response from the hon. Minister on this point.

I would like to just quickly mention two or three points, which are related to animals or livestock. One relates to feed and fodder development. It is a programme of the Animal Husbandry Department. The issue of feed and fodder has a significant bearing on the productivity of livestock in our country. But it is ignored. Due to increased pressure on land, there is difficulty in fodder development. There is a gap between demand and supply of feed and fodder. So, there is a need to establish a fodder bank. This is a proposal to the hon. Minister.

Another point is regarding the biotechnological project which is quite necessary at the present time. There is a proposal to enhance the facility of biotechnology research. Another point is regarding egg production. India is one of the three largest egg producing countries. There should be proper assistance to the State poultry farms and duck farms. There should be universal vaccination of

animals. When I talk of the programmes, there should be an awareness programme on behalf of the Ministry throughout the country. The awareness programme should be undertaken through the electronic and print media.

One of the major reasons for bringing forward this Bill is to facilitate import and export of animals and animal products. One of my questions is: How do we stop illegal export of cattle from our country to Bangladesh, to our neighbouring country, right from the borders of West Bengal and Tripura? Cattle are going across the border indiscriminately. It has a law and order impact also. So we should legalise the system. Why don't you legalise the system? Illegal export is going on from Tripura and West Bengal to the Bangladeshi areas. My point is, this provision or this Bill or this Act is enough. But it is our duty to implement it properly. With these words, I conclude.

श्री उपसभापति: प्रो. राम गोपाल यादव।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, इनकी maiden speech है।

श्री उपसभापति: Maiden नहीं है, वे पहले हाऊस के मैम्बर थे। नए term में maiden speech है।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में लाए हैं। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है क्योंकि पशुधन का इस देश की बहुत बड़ी population से बहुत नजदीकी रिश्ता है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग पशुधन पर निर्भर रहते हैं, अपना जीवनयापन करते हैं। लेकिन, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि इतना महत्वपूर्ण विभाग, Animal Husbandry, होने के बाद भी, इस पर sanctioned plan outlay में जो allotment है, वह निरंतर कम हो रहा है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में Animal Husbandry का शेयर total outlay का .48% था, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में घटकर .28% रह गया और 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में भी 2007-08 में भी यह .28% ही है। तो जिस सैक्टर से लगभग ढाई करोड़ लोगों को देश में रोजगार मिल रहा है, जो total GDP का लगभग 6% revenue देता हो, उसके लिए केन्द्र सरकार का उपेक्षापूर्ण बर्ताव ठीक नहीं है। हालांकि यह राज्यों का विषय है, मैं जानता हूं और एक सीमा के अंदर आप मदद कर सकते हैं, सब राज्यों पर निर्भर करता है कि वे कहां और कितना करें, लेकिन राज्यों को भी मदद आपको ही करनी पड़ेगी और इसे आपसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझता, बहुत से लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि आप जिस back ground के हैं, आपने जो काम किया है, गांव से लेकर यहां तक काम किया है, तो आप बेहतर जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि गांव में किस भूमिहीन के घर में एक भैंस भी होती है तो उसी के दूध, दही और घी से वह पूरे परिवार को चला लेता है, अपने बच्चों को पढ़ा लेता है। मैंने as a teacher यह देखा है, ऐसे students को देखा है, जिनके मां-बाप के पास केवल एक गाय, एक भैंस थी, जिसके बल पर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और आज वे बहुत अच्छी जगहों पर और स्थितियों में हैं। तो देश के आम लोगों के जीवन के लिए जो इतना महत्वपूर्ण विभाग है, उसके लिए allocation ज्यादा होना चाहिए, यह मेरी आपसे गुजारिश है।

इस विधेयक के विभिन्न अंशों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं स्वयं इस कमिटी का चेयरमैन था और मैंने recommendation की हैं और उसमें एक recommendation जो हमेशा कमिटी ने की है, Mahboob Zahedi साहब थे, अब नहीं हैं, पश्चिमी बंगाल से लगातार लोक सभा के मैम्बर थे, वहां के Animal Husbandry Minister रहे और उनकी जीवनभर की यह इच्छा थी, हर बार हम लोग यह recommend करते थे कि जैसे ICAR है, उसी के पेटर्न पर इस देश में एक Central Veterinary Research Institute होनी चाहिए। अगर यह हो जाएगा, तो

independently जानवरों के इलाज के लिए ज्यादा अच्छी व्यवस्था हो पाएगी, नयी researches होंगी और रोगों को कंट्रोल किया जाएगा। Foot And Mouth Disease से पहले इतना ज्यादा नुकसान होता था, अब तो काफी कम हो गया है, लेकिन वह पूरी तरह से eradicate नहीं हुई है, उसका कोई full proof इंतजाम नहीं हो पाया है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब यह Foot And Mouth Disease हो जाती थी, खास तौर से दूध देने वाली गाय या भैंस को यह बीमारी हो जाती थी, तो पहली दिक्कत यह होती थी कि उसका दूध खत्म हो जाता था। जैसे ही Foot And Mouth Disease हुई, अगर वह गाय 5 किलो दूध देती है, तो इस बीमारी के होने पर, वह एक किलो दूध भी नहीं दे पाती थी और गरीब लोगों की आमदनी का जरिया खत्म हो जाता था। अगर ICBR जैसी कोई संस्था आप बना देंगे, हालांकि कुछ संस्थाएं हैं, ICAR में भी हैं, इसके लिए अलग से बरेली में IBRI है, लेकिन फिर भी इसके लिए ICAR जैसी कोई संस्था होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि पिछले 4 वित्तीय वर्षों से तो मैं ही इस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं और हमने इसकी रिकमंडेशंस की हैं, इससे पहले भी इस कमेटी की लगातार यही रिकमंडेशन आती रही, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है कि यह काम नहीं हो पा रहा है, यदि यह जो जाए, तो यह लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी होगा।

उपसभापति जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल दूध से और जानवरों के गोश्त से जो रेवेन्यू होती है, वह देश की दो बड़ी crops, यानी wheat and paddy से होने वाली रेवेन्यू से थोड़ी ही कम है। NSS और CSO के अनुसार वर्ष 2004-05 में animal husbandry से, livestock से जो आमदनी थी, वह 1,73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। जो विभाग इतने बड़े पैमाने पर देश को रेवेन्यू देता हो, उस पशु-धन और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपसभापति जी, आजकल तरह-तरह के रोग होने लगे हैं। जब हम लोग इस बिल पर डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने हिंदुस्तान भर के Veterinary Sciences से जुड़े हुए experts को बुलाया था और उनसे पूछा था कि ऐसे कितने रोग हैं, जो जानवरों में होते हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं हैं। तो हमें बताया गया कि ऐसे 42 रोग हैं, जो जानवरों में होते हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान में नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो जानवर बाहर से आते हैं, उनकी चैकिंग का कोई full proof इंतजाम नहीं है, अगर उन 42 रोगों में से किसी एक रोग से संक्रमित जानवर भी यहां आ जाता है, तो पूरे देश के लिए संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास उसके ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। हिंदुस्तान में केवल एक high level laboratory भोपाल में है, हालांकि वह दुनिया की इस तरह की 10 laboratiories में से एक है, लेकिन हिंदुस्तान का जो स्वरूप है, जितने बड़े पैमाने पर यहां पशु-धन है, दुनिया में सबसे ज्यादा भैंसे यहां हैं, दूसरे नंबर पर गायें हैं, तीसरे नंबर पर भेड़े हैं, चौथे नंबर पर Ducks हैं, पांचवें नंबर पर camels हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर जब हमारे पास पशु-धन है, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, उस दृष्टि से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बाहर से जो पशु आते हैं, देश के अंदर घुसने से पहले ही उनकी पूरी चैकिंग हो जाए....।

जिससे वह कोई ऐसा रोग लेकर इस देश में न आ जाए, जिससे हमारे सामने एक नया संकट पैदा हो जाए। अभी रासायनिक और जैविक तरीकों से जो रोग जानवरों से मनुष्यों में आ सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट या उनको रोकने का हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। जब सार्श दुनिया में आया तो कहा गया कि अब हिन्दुस्तान में भी आएगा, इसके लिए चिंता हो गई, लेकिन वह नहीं आया, पर उसका हमारे पास कोई इलाज भी नहीं था। हालांकि यह जो बर्ड फ्लू वगैरह हैं, इसके लिए तो हमारे भोपाल स्थित laboratory ने वैक्सिन बना भी दिए हैं, लेकिन उस वैक्सिन का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, उस वैक्सिन को ज्यादा दिन तक रख भी नहीं सकते हैं, इसलिए उसको खत्म करना पड़ता है।

[उपसभाध्यक्ष **(श्री प्रशांत चटर्जी)** पीठासीन हुए]

इस वक्त अकस्मात् असम में बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू आ गया है, इसको रोकने का इंतजाम तो है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर यह व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं है, इसलिए हमारी यह डिमाण्ड रही है कि देश के अंदर अलग-अलग regional इलाकों में भोपाल की तरह की laboratory होनी चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर आसानी से इलाज भी हो सके, रिसर्च भी हो सके और इस तरह के रोगों को फैलने से रोका जा सके। इस विधेयक में कई सारे ऐसे provisions हैं, जिनके लिए राज्य सरकारें आगे चल कर आपसे यह कह सकती हैं कि हमें बड़ी दिक्कत है, हमारे पास सीमित संसाधन हैं, हम कैसे इसे लागू कर सकते हैं। चूंकि देश में संक्रामक रोग एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, एक गांव से दूसरे गांव में फैलता है, एक जिले से दूसरे जिले में फैलता है, जिले की सीमा पार कर के राज्य में चला जाता है और एक राज्य से दूसरे राज्यों में चला जाता है। यह विधेयक इसीलिए लाया गया है कि अलग-अलग राज्यों में कई बार अलग-अलग तरह के कानून थे, पर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के जानवर में कोई रोग है और उस जानवर के मध्य प्रदेश में जाने पर पाबंदी है, लेकिन यह पाबंदी का कानून राज्य सरकार तो नहीं बना सकते थे, यह केन्द्रीय कानून के जरिए ही हो सकता है कि रोगी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह पर movement या एक राज्य से दूसरे राज्य में movement को रोक दिया जाए। यह बेहतर उद्देश्य है, इस बेहतर उद्देश्य के लिए यह विधेयक आप ला रहे हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को बड़े पैमाने पर veterinary hospitals खोलने पड़ेंगे, vaterinay doctors रखने पड़ेंगे और गांव स्तर पर जिनको सूचना देनी होती है कि वहां यह बीमारी हो गई है, उसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो राज्य सरकार आपसे कहेगी कि यह कानून तो लागू हो जाएगा, लेकिन इसको implement करने के लिए जो पैसा चाहिए, उसमें कुछ हिस्सा केन्द्र सरकार दे। यह हमेशा से होता रहा है। वह कहेगी कि उसमें वह कुछ मदद करें, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि यह इतना महत्वपूर्ण है, तो इसमें आपको कुछ allocation बढ़ाना चाहिए। इस विधेयक में कुछ दंड के भी provisions हैं। अगर कोई सूचना नहीं देता है, तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन इन सबके लिए practically तमाम सारी दिक्कतें हैं। मैं उसका जिक्र यहां नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पशु धन पर या animal husbandary के लिए जो allocation कर रहे हैं, उसको आप बढ़ाइए। यह कानून बहुत अच्छा है, सब लोग कहेंगे कि यह कानून बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप इसका allocation नहीं बढ़ाएंगे, तब तक यह कानून धरातल पर निचले स्तर तक लागू ही नहीं हो पाएगा। आज आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर जो भी veterinary hospitals हैं, उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। आदमी के लिए जो अस्पताल हैं, तो तो नए-नए हैं। अब आप दिल्ली में देखिए, लोग अपोलो में चले जाते हैं, लेकिन जानवरों के लिए जो अस्पताल हैं, वे जब नए बनते हैं, तब एक-आध साल तक तो ठीक लगते हैं और एक-दो साल के बाद उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। अब tendency ऐसी हो गई है कि doctors गांवों के अस्पताल में रहना ही नहीं चाहते हैं, Veterinary doctors भी वहां नहीं जाना चाहते हैं, वे भी चाहते हैं कि कहीं बड़े शहर के आस-पास हो तो जाएंगे। वह भी चाहता है कि किसी बड़े शहर के आसपास कहीं हो तो जाएंगे। लेकिन उनके जो कंपाउंडर पशु-धन सहायक होते हैं, वे ही उनको देखते हैं। तो वे ही डाक्टर हैं किसानों के लिए। वहां डाक्टर्स हैं ही नहीं। न दवा है, न डाक्टर्स हैं, बिना डाक्टर के ही चलते हैं। तो आप इंतजाम कर देंगे, कानून बना देंगे। इसमें सारी व्यवस्था है कि जिसका जानवर संक्रामक रोग से बीमार हो जाए, तो वह उस अधिकारी को सूचना देगा और वह अधिकारी उसकी व्यवस्था करेगा। उसको अलग करने का काम तो जानवर के मालिक का ही है। लेकिन एक चीज पर मैं खास जोर देना चाहूंगा तथा इस पर ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात है। आदमी जब बीमार होता है तो उसको आसानी से अस्पताल ले जाया जा सकता है। लेकिन जब जानवर बीमार होता है तो सबसे बड़ी समस्या किसान के पास, उस गरीब आदमी के पास यह होती है कि वह उसको अस्पताल ले कैसे जाए। इसलिए इस काम

के लिए मोबाइल वेन होनी चाहिए। डाक्टर मय दवा के मोबाइल गाड़ियों से गांव पहुंचे और वहां उसको प्रोपर ट्रीटमेंट दें। ऐसी व्यवस्था करवाने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करे, तो यह बहुत बड़ा काम होगा और आप जो कानून ला रहे हैं, इस कानून का भी सदुपयोग हो जाएगा, क्योंकि अभी दिक्कत यह हो जाती है क्योंकि हमने तो देखा है तथा मैंने तो स्वयं गाय चराई हैं, भैंसे चराई है, इसलिए मैं जानता हूं कि जब फुट एंड माउथ डिसीज हो जाता था तो किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत मुश्किल हो जाता था। कुछ तो ऐसे रोग होते हैं जिनको हम लोग जान ही नहीं पाते थे क्योंकि लगता था कि आज जानवर ठीक है, जुगाली कर रहा है। लेकिन जब आदमी समझता था कि आज यह कुछ सुस्त सा है, तो तब तक वह काफी बीमार हो जाता था और दो दिन में वह खत्म हो जाता है, जिसके बारे में मालूम ही नहीं पड़ता था। जब कभी वह गिर जाता है तो सोचा जाता है कि कहीं से डाक्टर बुलाइए और डाक्टर के आने तक गांव का आदमी जो कुछ जानता है वह इलाज के तौर पर उसको थोड़ा बहुत दे रहा है। यही इलाज है। तो अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट से लैस मोबाइल वेन की व्यवस्था कर देंगे तो अच्छा होगा। एक जिले में जितने ब्लॉक हैं, तथा ब्लॉक में भी एक-एक हो। अगर राज्य सरकारें आपकी मदद से करें तो इससे लोगों का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है और पशु धन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों पर काबू भी पाया जा सकता है और पशु धन के स्वामियों को राहत भी दे सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय मंत्री जी को विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ ही आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, जिसके लिए आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल यहां लाया गया है, उसके पीछे जो मंशा है, उस मंशा की मैं भी प्रशंसा करता हूं और उसकी ताईद करता हूं। लेकिन इस पर अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक शिकायत माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी के माध्यम से मेरी यह शिकायत सरकार से भी है। विधेयक का जो प्रारूप हम लोगों को हिन्दी में दिया जाता है उसकी भाषा ऐसी रहती है कि उसके लिए ऐसा लगता है कि शब्द कोष अपने साथ लेकर के आना पड़ेगा और पता नहीं कि शब्द कोषों में भी ऐसे शब्दों के अर्थ मिलेंगे या नहीं। सरकार की जो भाषा है तथा जो बोलचाल की भाषा है, उसके बीच में कोई रिश्ता, कोई संबंध है नहीं। माननीय मंत्री जी सरकार के बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं और विधि मंत्री जी भी उनकी बगल में बैठे हुए हैं, उनका विधेयक भी मैं देख रहा था मेरा उनसे अनुरोध होगा कि कम से कम भाषा के मामले में थोड़ी सावधानी बरती जाए। भाषा ऐसी चीज नहीं है जिसको घर में बैठ करके गढ़ा जाए। भाषा जनता के बीच से, उसके व्यवहार से निकलती है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस शिकायत के साथ, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा कि इस विधेयक के पीछे जो मंशा है, उस मंशा का मैं समर्थन करता हूं। बहुत ज्यादा मुझको जानकारी नहीं थी, अभी भाई राम गोपाल जी बोल रहे थे, कई चीजों के बारे में हमको जानकारी मिली और उससे ज्ञानवर्धन हुआ। जब इन्होंने बताया कि पशुधन से दूध और मांस के बदले में जो आय है, वह एक लाख 73 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की है। विडम्बना इस बात की है कि जो क्षेत्र इतनी बड़ी आमदनी दे रहा है, देश का जो जीडीपी है, उस जीडीपी में जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए जो अलाटमेंट है, वह 0.48 परसेंट का है। यह सही है, जो हमारे भारत का विधान है, जो हमारे देश का संघीय ढांचा है, उसमें राज्य सरकार की जवाबदेही है कि सरकार जो विधान बना रही है, उसको वह लागू करे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार के किस बलबूते पर आप यह करने जा रहे हैं। इसके पीछे आपकी बहुत पवित्र और शुद्ध मंशा है, उसको कैसे लागू कर सकते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता है। मैं बिहार से आता हूं और बिहार सरकार में जो वित्त मंत्री हैं, वह उप-मुख्य मंत्री भी हैं। मैं उनका अखबार में बयान पढ़ रहा था कि छठा वेतन आयोग जो लागू हुआ है, उसको अगर बिहार सरकार लागू करेगी, तो पांच हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बिहार सरकार पर पड़ेगा। यह सिर्फ

बिहार सरकार का ही मामला नहीं है, सारी राज्य सरकारों का मामला है। इतना बड़ा क्षेत्र है, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप उस पर एक परसेंट भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार आंख मूंदकर, बिल्कुल उदार ह्दय से लोगों की तनख्वाह बढ़ा रही है। पचास हजार, साठ हजार, सत्तर हजार, रुपया महीना एक कलेक्टर की तनख्वाह होगी और जिस जिले में वह कलेक्टर होगा, उसकी 70-75 फीसदी जनता 1400, 1500 रुपये महीने में काम करती है, इतनी गैर-बराबरी के बीच में वह काम करेगा, इसको आप कैसे contain कर पाएंगे, कैसे इस देश के गरीबों का उद्धार कर पाएंगे, यह हमारी समझ के बाहर की बात है। इसलिए बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध मंशा के बावजूद हमें संदेह होता है कि आप इसको लागू कर पाएंगे।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि संक्रामक रोग पशुओं को नहीं हों, इसके लिए जो टीका है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और रोग हो जाए, तो उस रोग के निवारण के लिए जो चिकित्सा है, जो इलाज है, वह भी उतना ही महंगा है। जो एक जानवर, दो जानवर रखकर काम करने वाले लोग हैं, हमारे यहां बहुत सारे गरीब लोग हैं, पूरे देश में, गांव के इलाके में, जब दूध देने वाले जानवर का दूध सूख जाता है, तो बीच के पीरिएड के लिए लोग जानवरों को अधिया पर, बटय्या पर ले आते हैं, अगर कोई संक्रामक रोग उनके पशु को हो जाता है, तो वे कहां से उसका खर्चा ऐफोर्ड कर पाएंगे। उस इलाके में कोई संक्रामक रोग हो गया, तो उसके टीकाकरण के लिए वे लोग पैसा कहां से लाएंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम लोगों को खोजना पड़ेगा। हमको लगता है कि जो दवाई बनाने वाली कम्पनियां है, उनके दामों पर नियंत्रण रखा जाए, उनके दामों पर अंकुश रखा जाए और टीका को सब्सिडाइज्ड किया जाए। अगर आप टीका को मुफ्त में नहीं दे सकते हैं, तो उसको सब्सिडाइज्ड कीजिए और उसके दाम के बोझ का एक हिस्सा सरकार भी वहन करें। हमें इस बात से खुशी होगी कि टीका लोगों को मुफ्त में मिले, अगर मुफ्त में नहीं मिलता है, तो उसका कुछ बोझ सरकार को भी वहन करना चाहिए। मेरा यह एक सुझाव है।

जो गैर पालतू जानवर हैं, जैसे कुत्ता है, हमारे यहां बिहार में एक नीलगाय है, बिहार में और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में नीलगाय हैं। हमारे मन में यह सवाल उठता है कि ऐसे जानवर को कोई ऐसा संक्रामक रोग हो जाए, जिससे जो पालतू जानवर हैं, उनमें भी वह रोग फैले, उसको आप कैसे रोकेंगे? इसलिए हमको ऐसा लगता है कि संक्रामक रोगों से बचाने के लिए जो आपने सूची जानवरों की बनाई है, उस सूची में ऐसे जानवरों को भी शामिल किया जाए, जो हमारे यहां हैं, लेकिन वे पालतू जानवर नहीं हैं, क्योंकि उनसे भी संक्रमण का खतरा हमारे पालतू जानवरों को होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि ऐसे जानवरों को भी सूची में शामिल किया जाए क्योंकि बिहार तथा उत्तर प्रदेश के किसान नीलगाय की वजह से परेशान हैं। इसके अतिरिक्त हमें कुछ खास बात नहीं कहनी है। हमें उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी को जो हमने सुझाव दिए हैं, उनको शामिल करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं प्रो. राम गोपाल यादव जी का कि उन्होंने स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बहुत सी बातें कही हैं। मैं उनके प्रति आदर रखते हुए भी यह कहना चाहता हूं और जो कुछ हमारी भावनाएं, इस देश में पशुधन के बारे में और विशेषकर गाय के बारे में हैं, गोवंश के बारे में हैं, उनको ध्यान में रखकर, यदि स्टेंडिंग कमेटी ने उसको अलग प्रावधान के रूप में रख कर सोचा होता, तो इस देश की बहुत बड़ी समस्या को हल करने में सहायक होते। हम सब को मालूम है कि इस देश में गोमूत्र से हजारों लोगों की चिकित्सा हो रही है। हमारे यहां गोबर पवित्र माना जाता है। अभी जो हमने सारी बातें कही हैं, जो माननीय मंत्री जी ला रहे हैं, उसका भी एक आधार दुनिया में मान्यता प्राप्त करने के लिए है। यदि भारत का पशुधन इतना ज्यादा है, हम दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पन्न करते हैं, इतने पशु धन की हमारी श्रेष्ठता है, तो भारत को शरद

जी, आपके नेतृत्व में वह स्थिति लानी पड़ेगी, तब हमारे पास लोग मान्यता प्राप्त करने के लिए आएंगे। हम किसी के पास मान्यता प्राप्त करने के लिए नहीं जाएंगे। इतना विशाल पशुधन जिसके पास है, विशेष प्रकार की जितनी व्यवस्थाएं यहां पर हैं, अनेक सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं - मैं यादव जी फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बात को उद्धत किया, स्टेंडिंग कमेटी ने कहा है और इस बारे में सदन को भी जानना चाहिए कि ये बीमारियां आई कहां से हैं? यह साफ-साफ लिखा है कि बीमारियां वैश्विक वृद्धि के कारण आई हैं। हम दुनिया से प्राप्त बीमारियों के लिए अपनी सारी व्यवस्थाओं को कानून का रूप देना चाहते हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। मेरा आप से निवेदन है कि आपने अभी भी जो धारा-25 में सहज मृत्यु का प्रावधान किया है, मुझे भय है कि जब गौ पर इस प्रकार की बात होगी, आपको स्मरण होगा और मैं याद भी दिलाना चाहता हूं, यहां पर कानून मंत्री जी भी बैठे हैं, जिस संविधान के नाते आप अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात कर रहे हैं, उस संविधान की आप से मांग है कि आप सम्पूर्ण गोवंश की रक्षा करेंगे और संवर्धन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के एक विषय पर यह मान्यता दी है कि सम्पूर्ण गोवंश पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज जिस आवाजाही की बात कर रहे हैं, वह आवाजाही इसलिए है कि देश भर में गौवंश की हत्याबंदी पर एक केन्द्रीय कानून नहीं है। मेरी आप से यह मांग है कि इस पर कानून बनना चाहिए। जो मांस के लिए आवाजाही करते हैं, यह वृत्ति भारत के लिए उचित नहीं है। भारत जीवन मूल्यों का देश है और शरद जी आप से अच्छा इसको कोई नहीं जानता है। मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि आप इन बातों को ध्यान में रखकर कुछ अवश्य तथा उचित प्रावधान करेंगे, तो हम सभी लोग आपके आभारी होंगे। मैं फिर से यादव जी को उनकी अध्यक्षता में हुए बातों का स्मरण दिलाने के लिए धन्यवाद देता हूं और महोदय, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Standing Advisory Committee on Agriculture of which Prof. Ram Gopal Yadav was Chairman and I had the privilege of being a Member examined the first draft of this Bill three years back. At that time, the draft of the Bill was prepared as a knee-jerk reaction to the incidence of bird's flu in Maharashtra. Shri Sharad Pawarji had hurriedly gone and visited those places and successfully brought the epidemic under control. Health Minister had also gone there and helped in bringing the contagion under control. I am afraid, the draft of the Bill is still influenced by the kind of thing that had happened in Maharashtra at that time. We have had the recurrence of epidemics like that in Bengal, Assam and in other parts of the country also. But, the character of the problem has quite changed and I think, the last three years, from 2005 to 2008, have not been used by the Government before bringing this Bill to the Parliament. Number one, we are now facing a situation post terror attacks in Mumbai, 26/11, and it is recognised that the next time, the terrorists attack this country, it will not be by any of the methods they have used in the past and they are talking of a biological warfare and use of techniques that might affect the human food, as also the animal food. I am afraid, in 2008, the Bill is essentially a 2005 Bill and not a 2008 Bill. There is no provision regarding the carriage of viruses in vials, etc., and deliberate attempts to spread infection and contagion. It is a serious deficiency in the Bill. Sir, talking of contagious and infectious diseases, we have to think of three things. Number one, you can have infection and contagion from an animal to another animal of the same species. Secondly, you can have contagion from animal to other types of animals. Then, there can be contagion from animals to human beings. And, number four, and probably, the most important is the transmission of contagion and infection into food products that are produced from these animals that we are discussing about. Since the food products are involved, the question that we have to raise is

whether the mechanism that has been invented and that has been devised in the Bill is sufficient to control the infections and contagious epidemic. There are few provisions in the whole Bill about really the prevention of the contagious diseases. There are about 14 clauses in it. I think, as in the case of terrorist attacks, we do not think so much of proactive measures that can be taken. We are thinking more of remedial actions or knee-jerk reactions to epidemic or incidents that have already happened.

The first question that I would like to raise is very closely associated because contagion comes from animals to food products. When we discussed here the food safety Bill, the question that was raised was whether the Food Processing Ministry was the best Ministry for administering that Bill. I had taken the position that the Health Ministry would be the most appropriate Ministry to handle that. The first question that I would like to raise here is whether the question of contagious and infectious diseases should be handled by the Ministry of Agriculture, or whether the Ministry of Health would not be a more appropriate agency. If there had been, as Prof. Ram Gopal Yadavji pointed out, an Indian Council of Veterinary Research and if we had adequate infrastructure in the whole of the country under the Ministry of Agriculture, then there would have been possibly some justification for keeping it under the Ministry of Agriculture. As it is, I think, we need to reconsider : should this Bill not be executed and implemented by the Ministry of Health rather than the Ministry of Agriculture?

Then, the third point that I would like to make is that the impression given by the reading of the Bill is that we presume in case of animals that all contagious and infectious diseases are necessarily fatal and, therefore, what we try to do is culling out. Now, the word that is used here in Clause 25 of the Bill is 'euthanasia'. I think it is a very wrong word to use. In the Oxford Dictionary, the word 'euthanasia' means killing of a man who is suffering from an incurable disease. But the practical use and many legislations on the subject have given it a different connotation. It means that you have obtained the consent that the culling is being done or termination is being done on the suggestions and the request from the person concerned. In this case, Sir, in most cases, we shall be culling the animals – not on the request of the animal because dumb animals cannot express themselves because we want to stop the spread of the infection. So, for 'culling' of an animal in order to stop the spreading of infection, is not proper and you will have to devise another word. Euthanasia is certainly not the right word, and, I think, in clause 25, the word 'euthanasia' ought to be replaced, as one of my colleague also suggested, by a simple word 'culling'. You don't need to use a word that is not commonly understood, and, even if it is understood, it is not understood in the proper sense.

Sir, the next point, which I would like to make is about the infrastructural development. Since the occurrence of bird flu in Maharashtra, we had three years to create laboratories, to make hospitals etc. Nothing has been done, and, even today, as Dr. Manaklao was pointing out, at a place like Jaipur, the blood samples have to be flown to Bhopal and it takes months together before you know whether the animal is actually infected. So, this time should have really been used for creating infrastructure. Sir, with regard to the important part of the infrastructure – as Mr. Ram Gopal Yadavji pointed out, for years, the Standing Committee on Agriculture has been suggesting its importance – is creating the Indian Council of Veterinary Research, which has not happened.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Mr. Praful Patel, I can listen to your conversation from the Chair. Please. ...*(Interruptions)*... Please continue, Mr. Joshi.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: This very morning, there was a question and it was pointed out once again that establishment of a separate Indian Council of Veterinary Research is a very important thing. Today, again, the Standing Committee on Agriculture has emphasised the fact that it is necessary to create this ICVR. We were told in the Standing Committee, it may or may not be factually correct, that the important thing is that the ICAR is very jealous of its own sovereignty, jealous of its domain and has been opposing the creation of ICVR. If so, I would humbly submit to the hon. Minister of Agriculture that before starting the implementation of this, we should create the ICVR and the necessary infrastructure that goes with the successful and efficient implementation of this particular Bill.

Sir, the import of animal products and animal food is the last item, which I would deal with. I had to deal with that as the Chairman of the Task Force on Agriculture. We had a very serious problem. In the United States, people prefer eating for their food the chicken breast and they do not like eating chicken legs while, in India, chicken legs are extremely popular.

We faced a serious problem because the United States was trying to literally flood India with the chicken legs that they do not use, in any case. We made an enquiry about it as to how is it that Australia and New Zealand have faced this problem. And the answer that we received from New Zealand authorities was that since their chicken varieties were not imported from the United States, they did not face this problem of getting any contagion from the import of chicken breast from the United States.

Unfortunately, Sir, in India, most of the poultry industry, as it has been developed, has been developed on the basis of imported varieties, and, therefore, India is particularly susceptible to being affected by all imported food items. Sir, the next point is about the food products.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Please conclude.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: One minute, Sir. Since the responsibility of executing the Food Safety and Standards Bill has been given to the Ministry of Food Processing Industries, I would recommend to the Minister of Agriculture to take it up with the Cabinet and make the Ministry of Health the responsible Ministry for the implementation of this Bill. Thank you.

SHRI SANJAY RAUT (Maharashtra): Sir, I rise to speak on the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Bill, 2005.

At the outset, I would like to thank the hon. Agriculture Minister for taking care of the animals who suffer from any scheduled diseases and for the measures provided in the Bill to eradicate them with a complete check to its spread from one State to another State.

Sir, I am happy that the Bill covers many of the important aspects with respect to animal health and welfare, infectious and contagious diseases and protection of public health. However, I would

like to suggest some points which may be considered for incorporation in the Bill.

One, the Bill should provide a scope for animal registration/flock registration and necessary funding for the same.

There should be scope for national animal health information system for creating a national level animal health database.

There should be separate central veterinary institute like Indian Council for Veterinary Research in line with the councils such as the ICAR, the ICMR, etc., for better funding and research, development and education activities.

There should be a provision for national level animal health commission or zoonoses commission which can take the overall responsibility of regulating and monitoring infectious and contagious zoonotic animal diseases, and in emergency situation, it can take care of the threats from biological weapons/bio-terrorism.

Sir, there should be scope for establishing good research and diagnostic laboratories, vaccine research institutes, and veterinary drug research centres for some of the most important chronic infectious and contagious animal diseases, such as brucellosis, tuberculosis, para-tuberculosis, etc.. They are required because the farmer cannot bear the treatment cost of the diseases, and also he loses the productivity of the animal. Therefore, funding from the Government is required to take care of such diseases in animals.

There is a need to create different zones and compartments for the prevention and spread of animal diseases and also for creation and declaration of disease-free zones, disease-controlled areas, disease-infected areas and eradicated areas.

There is a need for national networking of laboratories and multi-sectoral coordination and cooperation, especially veterinary medical linkages.

As the Bill replaces the Glanders and Farcy Act, 1899, the Dourine Act, 1910 and any law of any State inconsistent with the provisions of the Bill, there should be a provision for compensation to the owner of the animals/birds where the animals are euthanized/birds are destroyed in the interest of public health.

The Bill does not speak much about regulatory measures for disposal of biological/hazardous waste. Therefore, there is a need for its safe disposal generated from animal enterprise, research and other activities.

Sir, the Bill, when passed, is going to help to control animal diseases of public health significance on a national basis and promote import and export of animals and animal products by meeting India's international obligations.

I am sure that these suggestions, if incorporated in the Bill, may make it more comprehensive and bring about scientific and systematic changes in the overall management of animal healthcare system as a whole.

Thank you, Sir.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, I stand here to support the Bill. I would like to congratulate the hon. Agriculture Minister on bringing the Bill. After a long journey of three years, today, the Bill is introduced in the Rajya Sabha. Sir, the Bill is introduced at the time when Assam is suffering from bird flu. It is a big problem in Assam. The bird flu affected almost every bird of Assam.

Sir, our village economy is totally based on agriculture and poultry farming. Floods have already created a havoc in Assam. Due to heavy floods, lakhs of people have become homeless in Assam, lakhs of hectares of cultivable land have totally been destroyed and thousands of animals have been killed. It has very badly affected the economy of Assam. As a result, poor people are losing everything in Assam. They have no rice to eat, they have no water to drink, they have no clothes to wear and they have no homes to stay. This is the condition of the poor people of Assam due to heavy floods. Now, after floods, birds' flu has created a havoc in Assam. As already stated by me that the economy of our people, particularly at the village level, is totally based on the domestic poultry farming only. Due to the bird flu, already the State Veterinary Department in Assam has started a culling operation as a result of which more than 4 lakh birds have been culled in Assam which affected the economy of Assam very badly. At this crucial juncture, we need assistance, special package, special help from the Union Agriculture Ministry. Sir, as I mentioned earlier, I would like to request that the Central Government should come forward to help Assam at this crucial juncture by providing a special package, including the setting up of a Bhopal like diagnostic laboratory in Assam because Assam is the hub of the north-eastern region. The north-eastern region consists of 8 States, namely Assam, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Sikkim, Manipur, Arunachal Pradesh and there is no research laboratory in the north-eastern region. Guwahati being the hub of the north-eastern region, I hope, the hon. Minister will consider this idea and at this crucial juncture and at this particular time, definitely our dynamic Agriculture Minister is going to open a research laboratory in the north-eastern region. And Guwahati being the hub of the north-eastern region, definitely, the Agriculture Minister is going to set up this laboratory in Guwahati.

Sir, it is known to us that communicable diseases like TB and bird flu spread from animals to human beings. The Government should conduct a veterinary research. By supporting this Bill, I would like to request the hon. Minister to kindly set up a separate Indian Council of Veterinary Research by separating it from the Indian Council of Agriculture. I hope, looking at this region, this Government, particularly the Agriculture Minister, is going to take very serious steps towards Assam and he will come forward to help the Government of Assam and the people of Assam. At this crucial juncture, they have already culled more than 5 lakhs birds in Assam, but due to the shortage of machinery, due to the shortage of expert people, the process is going at a very slow pace. So, I would like to request the Government to send more teams to Assam, more experts to Assam with sufficient funds, with sufficient medicines, with sufficient budget, and I hope, the Minister will consider it. With these words, I support this Bill.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले अखबार में, टेलीविजन पर और बहुत सारे दूसरे माध्यमों से आया कि मुर्गियों में वायरस आ गया है। उसके बाद सारे प्रदेश के मुर्गी पालकों को, सब लोगों को उन्हें मारने का आदेश हो गया। एक अखबार में आया एक गरीब आदमी का, बहुत गरीब आदमी का, जो

मुर्गी पालन करता था, उसका मुर्गी के साथ फोटो खिंचकर के सामने आ गया। अगर यह कानून पहले बना होता, तो शायद उन लोगों को राहत जरूर मिल गई होती। प्रिवेंशन जो है, वह ज्यादा क्योर होती है, लेकिन लगता है कि उसके बारे में पहले से कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो हमारा पशुधन है, उसके बारे में पहले से ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो कानून लाया गया है, यह सचमुच में बहुत सराहनीय है और पशुधन के प्रति जो आपकी संवेदना है वह बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं, जिनसे हमें लगता है कि जो पशुधन रखने वाले लोग हैं, जो मेले में व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आप कानून बना कर राज्यों को भेजेंगे और राज्य उसका पालन करेंगी। जैसा आपने इसमें कहा है कि हम पशु को मेले में तभी जाने देंगे, जब उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र उसके साथ होगा। आप तो जानते होंगे कि अगर पशु स्वस्थ भी है, उसे कोई बीमारी भी नहीं है, तो भी उसको व्यापार-मेले में ले जाने में क्या कठिनाई होगी? जो पशु-पालक है, उसको अपने जानवर को मेले में ले जाने में क्या परेशानी होगी? किस तरह का करप्शन वहां चालू होगा? इसलिए इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जो आपने चेकपोस्ट लगाया है, उस पर भी विचार करना चाहिए।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कुत्ते, बिल्ली सबका इसमें दिया है। इस मुल्क में मेरे ख्याल से हजारों कुत्ते ऐसे हैं, जो पालतू नहीं हैं, लेकिन सड़कों पर घूमते रहते हैं। अभी तक आपने उन कुत्तों के लिए कोई ऐसी दवा देने का प्रावधान नहीं बनाया है। लावारिस बच्चों के लिए तो ऐसा कुछ बनाया गया है कि हम लोग उनको कहीं गृह में रखेंगे, लेकिन उन कुत्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये कुत्ते जब काटते हैं, तो उससे वायरस फैलता है, बीमारी हो जाती है और जब हॉस्पिटल में जाकर पूछते हैं कि कुत्ते के काटने की कोई दवाई है, तो कहा जाता है कि हमारे पास नहीं है, वह आउट ऑफ स्टॉक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो लावारिस कुत्ते हैं, जैसे आपने आदमी के बच्चों के लिए पल्स पोलियों का इंतजाम किया है, ऐसी ही कोई एक योजना इनके लिए भी होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**... जी, एंटी रेबिस। जो जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, इनके बारे में ऐसा कुछ बनाना चाहिए, इसके लिए किसी को एम्बेसडर बनाकर टी.वी. पर लाना चाहिए, जैसे पल्स पोलियो में आ जाते हैं हमारे अमित जी। तो पल्स पोलियो में भी आपने दिया है, इसमें भी जानवरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जानवर को तो बोलने का नहीं है, वे हल्ला नहीं कर सकते, उन पशुओं के मालिक ही हल्ला कर सकते हैं। तो इसके लिए एम्बेसडर बनना चाहिए और अखबारों में, टेलीविजन में इनके बारे में आना चाहिए, यानी अगर आप पशु रखे हैं, कुत्ता रखे हैं, बिल्ली रखे हैं, आपके आसपास में हैं, तो उनके लिए सही इंतजाम होना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात और रखना चाहता हूं। वह यह है कि मैं मांसाहारी नहीं हूं। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं और मैं मांस-मछली नहीं खाता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। पहले एक प्रथा थी कि कोई बकरी या खस्सी काटता था तो उसको स्वास्थ्य विभाग से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। जानवर का चाहे जो भी डाक्टर हो, उस पर उसकी मुहर लगती थी। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: बकरी नहीं कटती है।

श्री राजनीति प्रसाद: लोग बकरा ही नहीं बकरी भी काटते हैं। आप कहां हैं? बकरीद में तो बकरी भी काटते हैं।

सर, उस पर मुहर लगती थी। उसका क्या मतलब है, यही कि उसमें कोई बीमारी नहीं है। इसे खाने वाले जो लोग होंगे, उनको बीमारी न हो जाए, इसका खयाल उसमें आता था, लेकिन वह मामला अब खत्म हो गया। अब मैं एक बात और इसके बारे में इनको कहना चाहूंगा कि इसके बारे में भी जरूर विचार कीजिए। इसमें भी कड़ा प्रोविजन कीजिए कि कोई बकरा खाता हो या खस्सी खाता हो या बकरी भी खाता हो, तो उसमें भी कोई मुहल लगानी चाहिए तथा कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ...**(व्यवधान)**... सर, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Your time is over. Extra time!

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मेरा समय है, नहीं तो समय के बाद मैं नहीं बोलता हूं।

सर, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। हम किसी को खाने से मना नहीं करते। वह मछली खाये या बकरी खाये। लेकिन, शहर में उसे प्रदर्शित किया जाता है और उसको लटकाकर आम लोगों के बीच में रखा जाता है। ऐसा कैसे होता है? उसके बारे में जरूर कुछ करिये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम खस्सी को लटकाकर रखिए। हम अहिंसा के पुजारी हो सकते हैं, लेकिन हम किसी को उसे खाने से मना नहीं करते। अगर किसी को यह खाना भी है, तो सड़क पर जो उसको एकदम लटकाकर रखा जाता है, तो उसके लिए भी कानून में कुछ करना चाहिए। उसको लटकाया जाता है और जिसको जो चाहिए वह काट कर दे देते हैं। इससे मन थोड़ा दुखी हो जाता है। आप इसको रोकने के लिए भी कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिये।

सर, आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग दूध के बहुत शौकीन हैं, हम लोग दूध पीते हैं। **...(व्यवधान)...**

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): यह बिल्कुल नहीं लगता कि आप दूध पीते हैं।

श्री राजनीति प्रसाद: नहीं, नहीं। वह तो स्ट्रक्चर होता है **...(व्यवधान)...** एक मिटन। मुझे बोलने दीजिए। हम लोग दूध के प्रेमी हैं। हम चाहे रसगुल्ला खायें, चाहे छेना खायें या कुछ भी खायें, लेकिन उसमें एक नई चीज ईजाद हुई है। वह चीज यह हुई है कि जो गाय दूध कम देती है, ज्यादा दूध नहीं देती है, तो उसको सूई लगा देते हैं। पता नहीं आपको यह मालूम है या नहीं, लेकिन उसको सूई देते हैं। उसे दूध निकालते समय ही सूई देते हैं। उससे ज्यादा दूध आता है, लेकिन वह बहुत खतरनाक होता है। आप उसके बारे में भी जरूर सोचिए। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो, हम लोगों को शुद्ध दूध मिल पाएगा। एक और अंतिम बात **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री प्रशांत चटर्जी): दो बार हो गया 'अंतिम बात'।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मैं जो ज्यादा समय लेता नहीं हूं। अंतिम बात यह है कि आपने एक कानून बनाया है कि अगर कोई गाय लॉट में है और अगर किसी को disease है, तो उसको अलग रखने की व्यवस्था की जाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसके पास जगह कहां है? वह इसको कहां रखेगा और कैसे रखेगा? कौन-सी जगह में उसकी बीमारी का इलाज होगा?

अंत में, मैं एक और बात कहकर समाप्त करता हूं। आजकल Veterinary doctors की बहुत कमी हो गई है। वे जल्दी मिलते नहीं हैं। आपने जो कानून बनाया है, उसको Veterinary doctors ही कार्यान्वित कर पाएंगे। आदमी के तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन Veterinary doctors की कमी है, इसके बारे में भी आप जरूर कुछ करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने एकाध मिनट ज्यादा समय लिया, इसके लिए माफ करिएगा। धन्यवाद।

SHRI A.A. JINNAH (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I support this Bill. In Tamil Nadu, we call agricultural land as 'madu', that means wealth. We celebrated a day of thanksgiving to agriculturists on 1st day of *Thai*. Now the Tamil Nadu Government has announced it as the Tamil New Year Day. On this day, we give thanks to agriculturists who are working very hard. The next day is called 'thanksgiving day' for animals. Legally and officially, we are celebrating 'madu pongal'. Like this we give much importance to animals also.

In Tamil Nadu, there is a ritual of giving animals as offerings to temples. That is welcome. But these animals are not being taken care of properly because of scarcity of place. They have not been able to feed them properly and some of these animals die of diseases. The hon. Minister should see to it that the offerings given to the temples are taken care of properly by giving them enough space and enough food and shelter.

So far as the cow is concerned, our great national poet, Shri Bharathiar says, " ". (Hon. Member may please fill in the Tamil quotation) That means the cow which gives milk is a good animal because even the mother feeds only her children, whereas, the cow is giving milk to all human beings in the world. So, the cow is worshiped by people. Some people worship the cow. But, anyhow, they have to be protected. In Tamil Nadu, there is a disease called *'komari'*, foot and mouth disease, because of which a lot of animals die. They need to be protected from this disease.

Some of the poor farmers who don't have modern equipments are making use of bulls. Sir, a lot of students, every year, pass out after doing Veterinary Science, but they are not getting any jobs. They have opened their own clinics which are not of much use for the protection of animals. Therefore, I request the hon. Minister to provide them a separate employment scheme. They should be given Government jobs. In this way, we will get veterinary doctors who will protect our animals. With these words, I support the Bill.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I, on behalf of my party, thank the hon. Minister for coming forward with the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Bill, 2005. Although this Bill has come three years late, I hope people will be able to keep very effective control over various diseases in the livestock in Assam and in the country as a whole.

Sir, nowadays our State is suffering from 'bird flu'. It has taken an epidemic form. Already, the Rapid Action Force consisting of veterinary experts and other employees have culled three to five lakhs of birds in Assam. It is a communicable disease which may spread to human beings. The Government should take extra care to prevent further spread of the disease. The farmers are affected. It impacted the economy of Assam. Therefore, the Government should extend adequate compensation to the farmers. In Assam, almost all the districts, including Nalbari, Barpeta, Kamrup, Goalpara, Lakhimpur, Dibrugarh, Sibsagar, are badly affected. Although the Rapid Action Force has taken action, it is not adequate. Therefore, the Central Government should send an additional team of experts, especially from the Agriculture Ministry or the Health Ministry to control the situation.

Sir, I would also like to raise one more important point and that is about the migratory birds. In the months of November and December, lakhs of migratory birds come from Australia and Siberia to Assam. Now, a report has been published today in the newspapers in our State that these migratory birds are spreading various diseases which would affect the animals too. So, the Government should take necessary action on this problem as well. In fact, there is an obligation on the part of the Member Countries to provide information to the Office of International Affairs (OIA) regarding the status of animals, and these countries are expected to follow the guidelines on the control of animal diseases. And India too is a Member of the OIA. So, the Government should take it up this problem with the OIA so that it is taken care of.

4.00 P.M.

One more thing is that illegal trade in cattle on the Indo-Bangladesh border in Assam should be stopped. Due to this illegal trade, various diseases are spreading to the animals in our State. I would like to draw the attention of the hon. Minister to this problem and request him to address it as well.

With these words, I support this Bill.

SHRI AVTAR SINGH KARIMPURI (Uttar Pradesh): Sir, the discussion is going on very constructively, and I stand for making just one point. मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लानी है, क्योंकि जो प्वाइंट मैं उठाना चाहता हूं, वह किसी भी ऑनरेबल मेंबर ने अभी तक नहीं उठाया है और वह यह है कि जो 92 diseases की लिस्ट इस बिल में दी गई है, जो बीमारियां इसमें mention की गई है, उनमें AIDS का नाम नहीं है, जब कि बहुत से animals को HIV Positive पाया गया है। लेकिन इस लिस्ट में वह add नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि यह जो वर्ल्ड के सामने एड्स के HIV Positive का बहुत बड़ा challenge है, इसको इस लिस्ट में include कर लेना चाहिए, यह हमारी request है। आज जो हम देख रहे हैं the insemination is going on without proper testing of HIV positive or negative. So, my request is, it should be ensured that before insemination, the proper AIDS test, HIV positive or negative, it should be also declared, इसके बाद ही procedure adopt होना चाहिए। मैं तो सिर्फ इस बिल पर इतना ही सजेस्ट करना चाहता हूं, बाकी जो present प्रावधान किए हैं, वे अच्छे हैं। इसके लिए जो प्रॉपर infrastructure चाहिए, जो required है, उसको ज्यादातर States के ऊपर छोड़ा गया है और States के पास इतने sufficient fund नहीं होंगे, इसलिए वह ज्यादातर थ्योरी ही बन कर रह जाएगी। अतः इसके प्रॉपर implementation के लिए स्टेटों के लिए जो required fund चाहिए, मंत्री महोदय को केन्द्र की ओर से उसका प्रावधान करने के लिए efforts करना चाहिए। हमें इसके ऊपर result oriented efforts करना चाहिए। मेरा जो सजेशन है, वह बहुत गंभीर है। मैं चाहूंगा कि इसको इसमें include किया जाए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Thank you, Mr. Karimpuri. This was your maiden speech. Now, Mr. D. Raja is the last speaker on this Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Once there was a debate on our names. I am known as 'democratic Raja'. ...*(Interruptions)*... I have an imperial name. Sir, Tamil Nadu is one State which has fairly rich livestock. We have got good cattle and other birds. The bird flu that has spread in Assam has hit the poultry industry in Tamil Nadu. Tamil Nadu is one of the biggest centres for poultry in the country. I think, it is one of the biggest centres in the world also. Namakkal, it is the place where the poultry industry largely is present. There now more than several crores of eggs are not being exported. They are still in the poultries, and the poultry owners are being very much hit by this. During the recent floods and rains, thousands of cattle were perished. In this background, I would like to make a few observations. The UPA Government's Common Minimum Programme declares that public investments in agriculture will be stepped up. Even though the Government is at the fag end, I think, it covers the animal husbandry also. So, there, I think, the Government will have to seriously think of launching cattle insurance. As we talk about crop insurance, cattle insurance is also a must in the given situation. And, if you go by this Bill, there are many responsibilities. Of course, the State Governments have responsibility; the Central Government has a responsibility. But, whenever there is bird flu or some kind of anthrax, where large-scale cattle are affected, I think, it

has to be considered as a national disaster and how this issue can be addressed. When there is flood or a natural calamity, there is a Calamity Relief Fund. It has a proportion. The Central Government gives 75 per cent and the State Governments will have to give 25 per cent. On these lines, the senior Minister like Shri Sharad Pawarji, can initiate steps to provide some kind of special financial assistance to States. You can work it out because if you go through the Bill, you will find that the responsibility lies with both the Centre and the States. It has to be defined further. If the States face some financial constraints, the Centre will have to go to the assistance of the State Governments. The Centre will have to ponder over these problems.

The State of West Bengal was also very terribly affected once. Now, the State of Assam is affected, and, tomorrow, some other State can get hit by these kinds of disasters. So, the Centre's responsibility must be more.

There is the question of vaccines also. There is increasing privatisation in the production of vaccines and prices of vaccines are going up. I don't know whether ordinary farmers, or landless agricultural workers, who own a few animals, like cows, bulls etc., can go for purchasing such costly vaccines. The Centre must ensure that vaccines are made available at affordable prices to these people. There should not be any difficulty in doing this. There should not be any politics involved in this. Politics should not come in the way of defending or protecting our cattle and livestock. The Government can take serious and meaningful steps for protecting our animals and birds.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Having said this, I must also point out that India is known for its rich livestock, animals and birds. They contribute immensely to our economy. They also contribute to our culture, civilisation and day-to-day life. It has become imperative and we should see that our livestock is preserved, conserved and protected. So, I support this Bill. It is a very timely one. I must congratulate the Minister also. But, it has come at the fag end, so, it should not become some kind of a ritual. It should not be like this that something happens in Assam and the Government responds to it. It should not be like that. There should be a very consistent and a very comprehensive effort to preserve and conserve our livestock. Several years back, I had been to Vietnam. There I found that some of our experts from Haryana were helping the Government of Vietnam for rearing buffaloes. We had that tradition. Now, we are in a crisis due to many reasons. It is not due to our own difficulties also. We can't export some of the meat to other European countries. They put several conditions like hygiene and other criteria. That is why, maintaining the health of our animals and birds is important. If this Bill helps in fulfilling that, I will be very happy. I think the intention of this Bill is to preserve and conserve our cattle and livestock in the country. I hope with this perspective, the Government will address some of the concrete issues, which we find very difficult to handle in this given situation.

When the disease hits the livestock on a large scale, then, financial assistance should be given to the farmers by the Government. The other thing I pointed out was about vaccines. These are some of

the things which I wanted to mention. Many Members have already spoken on this. Even Prof. Ram Gopal Yadavji mentioned how animal husbandry has to be supported. He suggested that the number of veterinary colleges must be enhanced. He suggested that good quality veterinary centres and that zonal veterinary research centres must be established. With these suggestions, I would conclude and request the hon. Minister to respond.

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश): सर, एक मिनट का समय दे दीजिए।

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं।

श्री नन्द किशोर यादव: सर, मुझे half minute का समय बोलने के लिए दे दीजिए।

श्री उपसभापति: बस हो गया। Half minute में आप बोल नहीं सकते हैं, आप क्यों half minute बोलते हो। **...(व्यवधान)...** अच्छा, आप बोलिए।

श्री नन्द किशोर यादव: सर, सारे देश के अंदर जो पशु हैं, उनके रोगों को नियंत्रण करने के लिए इस विधेयक में तमाम बातें की गई हैं। मैं केवल एक चीज़ जानना चाहता हूं कि जाड़ों के महीने में जो दूसरे देशों से पक्षी हमारी झीलों में, नदियों में आते हैं, उनसे जो बीमारी आएगी, उसको रोकने का सरकार क्या प्रबन्ध करेगी? हमारे देश में पॉल्ट्री उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और जाड़े के महीने में विशेषकर अक्टूबर से लेकर जनवरी महीने में बर्ड फ्लू का ज्यादा प्रकोप रहता है। मुझे शंका है कि जो बाहर के पक्षी आते हैं, इन्हीं से यह बीमारी आती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो प्रवासी पक्षी बीमारी लेकर के आ रहे हैं, उनको रोकने का सरकार क्या प्रयास करेगी? बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SHARAD PAWAR : I am grateful to hon. Members from all sides for their valuable support to this Bill without any exception. There were lot of good and constructive suggestions made. Hon. Members wanted some of the suggestions to be incorporated in the present Bill, but that is not possible. The House is fully aware of the procedure, and unless and until specific amendments had been moved here, it was not possible for me to say whether I am in a position to accept them or not. But, surely, serious thought would be given to some of the suggestions which have been made here, and if possible, when we formulate the rules, we will be able to incorporate some of them in the rules.

I need not explain the importance of the agriculture sector for a county like ours. We have seen over the last few years that this is one sector that has been facing serious problems. We are targeting a growth rate of about four per cent. But, in the Tenth Plan, we could not achieve even two per cent. When the UPA Government came into power, a number of corrective steps were taken. In the last three years, we have seen that the growth rate has crossed four per cent. In this particular year, we have witnessed the farming community of this country produce the highest stock of wheat and rice and practically, we have succeeded in resolving the problem of food security. When I talk of a four or 4.5 per cent growth, I have to admit that the contribution of livestock sector is quite important in this particular growth. Animal husbandry and fishery are equally important sectors for the country.

Hon. Member, Shri Ramgopal Yadav has given certain figures about the value of the total output from livestock sector and the figure given is about Rs. 1,70,000 crores. If you look at the latest report for the year 2006-07, the total value of output from the livestock sector is Rs. 2,11,000 crores. I have not included the fishery sector here. In fact, last year the fishery sector's export alone was more than

8000 crores. So, our people do not realise the importance of this particular sector whether it is livestock sector or fishery sector. Now take the case of milk. The value of output of milk, the figure which I am quoting is of 2006-07, is Rs.1,44,386 crore. If you take the total income of paddy and wheat together, the income of milk is more than that of the paddy and wheat. That is the position. Another important aspect is that milk sector is providing jobs to the weakest sections of the society. It provides opportunity to women in a big way. I need not explain the importance of milk. But milk sector is one of the sectors which is providing a lot of jobs to the rural poor and that is why we have to give a lot of importance to this sector.

Poultry is one of the important sectors. India ranks fourth in the world in the eggs and broilers production. We also export eggs and broilers to some of the countries, especially in Gulf countries. We produce the highest milk in the world today. With this background, unless and until we provide sufficient attention to this sector I don't think we will be able to expect or achieve what exactly we are achieving from the agricultural sector. One of the points raised here is that the Agriculture Ministry is not giving equal importance or due importance to this particular sector. In fact, one of the major decisions which we have taken is that there is a separate Department for Animal Husbandry, Dairy and Fishery and this particular decision was taken by this Government. Earlier there was no recognition to the fishery. Fishery was always included in the animal husbandry. But we have accepted fishery as a separate sector. Though the Ministry is one, but there is a separate Department for Animal Husbandry, Dairy Development and Fishery. There is a separate Secretary and separate set-up for this particular Department. That is why I will request the hon. Members that they should not think that this particular sector has been totally neglected or this is strictly under the Ministry of Agriculture. Ministry is the same but this particular Department is altogether separate and enough attention has been paid to this particular sector. We have achieved many things in this livestock sector. We have tremendous wealth; we have tremendous youthful breeds, which are available in the country. An issue was raised regarding the importance of cow. In fact, there are a number of cow varieties, which are indigenous breeds and which are available in the country. In fact, some of our breeds have been taken by other countries and they have developed their own breed. Hon. Member from Andhra has raised a particular issue of Ongal breed. I recollect, three years back I had been to Brazil. On the main highway, I saw a big hoarding with a photograph of a beautiful cow, a very impressive cow, and it was written "This is the Ongal cow; we don't know from where it came to our country, but our country's rural economy has been changed by this particular cow." This Ongal cow was from Andhra. The breed was taken from Andhra. They have developed and improved it, and now it has become very important sector in Brazil. In Sao Paulo I was just watching television and on television I saw one channel where there was a ramp and instead of beautiful women, cows were coming. And, these were essentially cows from Ongal. ...*(Interruptions)*.... They are writing 'Ongal'. But, that is from your State. So, this shows the potential of this sector. Now, when I came, the Murra buffalo was mentioned here. This is one of the best varieties. When I had been to China and when I got an opportunity to interact with the Chinese Minister for Agriculture and Animal Husbandry, we were asking a number of other things like new seed variety, better quality of germ plasma to improve our own seed, etc. So, they asked me only one thing. They asked me, "We want Murra buffalo. We want to develop this Murra breed." I just asked them, "What do you know about

the Murra?" The Minister said, "In tomorrow's itinerary, you are going to visit one particular dairy and you will see Murra breed there." I asked, "From where have you bought this because we have banned the export of this breed?". They said that they had anyhow succeeded to bring from India to Pakistan, from Pakistan to some other country, and from some other country to China, and they were developing that breed. So, what I am trying to tell hon. Members is that there are number of good breeds which are available in our country. If we develop, if we pay proper attention, then this sector alone will get tremendous wealth and strength to the country and that is the reason we would like to give it more importance.

Now, what is this Bill? India is a member of the World Animal Health Organisation. The World Animal Health Organisation has taken many decisions. Practically, it was accepted that most of the member countries would implement their decision and they would introduce legislations to protect these animals from various types of diseases. Agriculture is a State Subject. But, we took advantage of the article 253 of the Constitution, which states, "Legislation for giving effect to international agreements Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other body." We took advantage of this provision and we have drafted this Bill. The objective of the Bill is to prevent spread of the economically important infectious and contagious diseases from one part of the country to another; to control and eradicate area within the country in order to reduce the economic losses on account of the major economically important infectious and contagious diseases of the livestock; and, to control the animal diseases of the public health significance on national basis and to promote import and export of the animals and animal products by meeting India's international obligation. The Government took this decision in the year 2005. I introduced the Bill in Rajya Sabha on 21st December, 2005. As per our practice, this Bill had gone to the Standing Committee. The Standing Committee had applied its mind. They had given many suggestions. Practically, 18 suggestions were given by the Standing Committee. Out of these, 10 have been incorporated in the Bill and in the rest of the cases, proper action will be taken at the time of formulation of the rules. These need not be incorporated in the Bill, but definitely, we are going to consider each and every suggestion, which had been made by the Standing Committee, while formulating the rules. I need not explain the salient features of the Bill because the Bill has already been there before the House and many hon. Members have given their views. Initially, I thought that nobody would pay any attention to the Bill, but I felt happy when hon. Members contributed from all the sides. I am quite happy that everybody has given it so much importance.

Hon. Member from Rajasthan, Dr. Narayan Singh Manaklao is very knowledgeable person about the horses. I got an opportunity to interact with him on the problem of the horses. The breed of Marwari horses is also one of the wealth of this country, and, we have taken certain decisions with regard to certain problems that this particular breed is facing.

He has referred to the issue of bird flu. In fact, many hon. Members have mentioned about it. We have seen this particular problem in the last four years. It started in Maharastra. It spread in one small

area of Surat District in Gujarat. We successfully controlled that thing.

Again, we have seen some problem somewhere in Manipur. We successfully handled that issue. Then, we have seen it again spreading in West Bengal. In fact, it had affected West Bengal's rural economy but with the help and the support of the West Bengal Government, many corrective actions had been taken and we were successful in controlling it. In the last few days, we are observing same problem in Assam.

The first occurrence of it in Assam was notified in respect of the village Rajabazaar, Block Hazo in Kamrup District on 27th of November, 2008. Since then, the infection has been detected in six more Districts. These Districts are Kamrup, Kamrup (Metro), Nalbari, Barpeta, Chirang, Dibrugarh and Bongaigaon. There are total 13 epicentres of this particular infection. We have discussed it with the local Government, and, whatever requirements were there, those have been provided by the Government of India, like different types of teams was one of their requirements. On 14th of December, 2008, a total of 118 R.R. teams in the various epicentres were carrying out the control and prevention operations.

Expected poultry to be culled in all the epicentres is somewhat about 5,25,000 excluding new epicentres of the infection indicated, as I have mentioned. Whatever is the compensation that we are supposed to pay, that amount is also provided, out of which, fifty per cent of the amount is provided by the Government of India and the rest of it is provided by the State Government. Whatever equipments and other precautionary measures which we are supposed to take, all these kits, all these sets, all these medicines have been supplied to the Government of Assam; and they are taking all precautionary measures.

In fact, yesterday, we have received a report from the High Security Animal Disease Laboratory where we had sent the samples from two villages, Narhatta Gram Panchayat in English Bazaar Block, District Malda, and, unfortunately, the report came positive of avian influenza.

The State has notified on that very day, that is, yesterday, to initiate control and containment operations within the three-kilometre radius of this particular village. The assessment of the poultry that we need to cull is also being made. The Government of West Bengal and the concerned staff is experienced in this, and, I am confident that they will be able to take all the precautionary measures. Whatever is their requirement, it is being provided by the Government of India. We are keeping a close eye on that.

On four occasions, we had seen how bird flu created serious problems throughout India and outside India. Our products were banned and our export was totally stopped.

The hon. Member, Mr. Raja, made a mention of Namakkal. It is a place which is a major exporter of broiler and eggs to a number of countries, particularly Gulf. The farmers from that area and from other States also heavily suffered because our export was totally banned due to international understanding. But we succeeded in handling the situation and export was again started.

Now, due to some problems in Assam and due to the problem which we found in Malda district yesterday, there might be some repercussion on India's export of eggs and other poultry products.

We are watching this type of situation. We are experiencing this type of situations. Until and unless we take some corrective action, it will be very difficult to control all these things. That is a reason why this particular Bill has been introduced.

A number of issues have been raised by some of our colleagues. Definition of cattle was one. In fact, I have checked it in the Oxford Dictionary. Cow is already incorporated there. Cow, bull, and bullock are there. Though in Hindi it is written ढोर, it makes no difference. We have not neglected cow.

The hon. Member from Rajasthan, Dr. Narayan, raised one particular experience of horses and Pushkar Mela. I will not be able to reply on this. But this particular problem which he has been facing is essentially handled by the State Veterinary Department. I am going to call the meeting of the Ministers of Animal Husbandry and Dairy Development. I definitely discuss this type of issues which the hon. Members are facing. I will request them to take the corrective action.

One point was raised that we have set up only one laboratory, which can assess these types of problems, and that is located in Bhopal. In fact, one laboratory is not sufficient. There was a demand when we started facing the problem in West Bengal. Last year, there was a demand that we should try to set it up in a decentralised manner. We have taken the decision to set up six BSL-III labs which has been approved under the World Bank funded project. Out of that, two labs are going to be set up. One in Kolkata and one in Jalandhar. Both the labs are expected to come in operation from March 2009. Whatever pressure is there in the Bhopal lab, but I will not be able to provide a special lab in Guwahati immediately. But, at least, Kolkata will be able to take care of the entire North-East at initial stage. We will think, at appropriate time, to provide this type of infrastructure in Guwahati also.

One of the issues raised here was regarding registration. We have made a provision in this legislation that when any particular area is affected with it, then inoculation should be compulsory. It was asked that it was not available. I will not be able to reply on that, but, definitely, I will collect the information. We have very important and very good vaccine producing companies available in our country. They always supply as per our own requirement. But in a particular problem which has been referred here, I will be happy to go in its detail, and I will try to take corrective action. Hon'ble Member, Shri Moinul Hassan, has raised the problem of foot and mouth disease about which a certain programme has been taken up. His request that we should take up these particular programmes in many districts has been noted, and I think, a special programme has been taken up just to control the foot and mouth disease, and we are implementing that programme for the last few years. There is improvement. But this is one of the important diseases which our cows are particularly facing. Shri Ram Gopal Yadav and many other hon. Members have given a suggestion that we are working under the Indian Council for Agriculture Research. Indian Council for Agriculture Research is one of the premier organizations which looks after crop, which looks after the livestock and which also looks after the fishery sector. There are more than 6,000 scientists who are working under the umbrella of this organization. This organization has contributed substantially in the agriculture and livestock sector in the last fifty years. There is a suggestion that this particular organization is essentially concentrating on agriculture and agriculture-related issues, and that is why

they are neglecting the fishery sector and livestock sector. In fact, I myself have gone in detail when this particular subject was raised, but my own observation is, that is not the situation. One hon. Member has suggested that there is a jealousy about the livestock sector in the ICAR, but that is not the factual position. There is no reason why to keep jealousy. There are separate institutions, there is separate scientific staff which is looking after the livestock sector or fishery sector and enough attention has been paid by the ICAR and the Government of India also. But I think the time has come to give a serious thought whether we should set up an independent organization, that is, on the pattern of Indian Council for Agriculture Research, and there is a demand that the Government of India should set up an Indian Council for Veterinary Research. I have not gone in detail yet. But I am seriously thinking to call a small group of experts to go in detail whether it is viable. If it is viable, in what way we should execute it, what will be the total investment and how it will be useful, and if we get the positive report, we will take immediate action and we try to fulfil the demand which has been raised by many other organizations outside the House and many hon. Members in the House also. I am fully aware that the Standing Committee on Agriculture has made this particular recommendation and I will definitely give a serious thought to this particular suggestion.

Hon'ble Member, Shri Sharad Joshi, has said that we have neglected some other areas. He referred to the Bombay problem and he rightly mentioned that tomorrow there is a serious threat of biological virus which might affect the country as a whole. In fact, there are many decisions. Firstly, the Minister for Agriculture is preferring a National Agriculture Bio Security System which will address biological issues in the plants and animals, and even in fishery. We have set up a National Disaster Management Authority. The NDMA has addressed the issue of bio-terrorism, including plants and animals pathogens. The NDMA will formulate appropriate rules to protect against the bio-terrorism. So whatever the worry which has been expressed here, I think, the Government of India has given a serious thought and I think we will be able to provide a certain mechanism which will protect the country's interest from these types of problems. Another issue which has been raised here is that it is an AIDs-like disease. In fact, as per my information, the list of diseases, which are indicated here, is not in the nature of infectious. In fact, there is no disease like AIDs in the, animals. There was, somewhat, near to AIDs, one particular disease, but that has, practically, disappeared from our country. That is why, I don't think, we should take separate precautions to control this particular type of disease.

There are many other suggestions. As I said, I will definitely incorporate some of the suggestions when I am going to formulate the rules. This Bill is a very useful Bill. It is true that we took practically three years, but one should not forget that as per the procedure, it has gone to the Standing Committee, and after getting the Report from the Standing Committee, it took a little bit time within the Department also in deciding what to accept and what not to accept. We have interacted with many experts and ultimately, we have come out with this formulation. And when we got this opportunity, which I do, to bring this legislation before this august House, I am sure, the way the hon. Members have supported this Bill, they will also pass this Bill unanimously. Sir, I commend the House to pass this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*...

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, I will take a minute. I want to know whether the veterinaries will be treated as 'professionals' and whether their private clinics will be designated as places where they can carry out these preventive activities and can also do the subsequent disease management.

SHRI SHARAD PAWAR: How many professionals are there? ...*(Interruptions)*... Sir, this is not a part of the legislation. These are administrative issues.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to provide for the prevention, control and eradication of infectious and contagious diseases affecting animals, for prevention of outbreak or spreading of such diseases from one State to another, and to meet the international obligations of India for facilitating import and export of animals and animal products and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In clause 2, there are two amendments (Nos.3 and 4) by the Minister.

Clause 2 - Definitions

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

3. That at page 2, *for* line 39, the following be *substituted,* namely, –

"newspaper or any other mass media and the means of local communication such as declaration in loud voice and by beating drums in the area:";

4. That at page 2, *for* line 48, the following be *substituted,* namely, –

"or designated as such in accordance with the qualifications, prescribed by the State Government."

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 3. There are three amendments (Nos.5 to 7) by the Minister.

Clause 4 - Reporting Scheduled diseases obligatory

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

5. That at page 3, *for* lines 11 to 13, the following be *inserted,* namely, –

"infective of a scheduled disease shall report the fact to the Village Officer or village panchayat in-charge, who may report the same in writing to the nearest available Veterinarian.

(2) The Village Officer shall visit the area falling within his jurisdiction for reporting any outbreak of the disease.";

6. That at page 3, line 14, *for* the bracket and figure "(2)", the bracket and figure "(3)" be *substituted.*

7. That at page 3, line 17, for the bracket and figure "(3)", the bracket and figure "(4)" be substituted.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 6 for consideration. There is one amendment (No.8) by the Minister.

Clause 6 -Notification of controlled areas and free areas.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

8. That at page 3, line 35, *for* the words "vernacular language", the words "vernacular language and by declaration in loud voice and by beating drums in the area" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clauses 7 to 14 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 15 for consideration. There is one amendment (No. 15) by the Minister.

Clause 15 - Inspection and detention of animals at check posts and quarantine camps.

9. That at page 5, line 38, the words "the Director" be *deleted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

Clauses 16 to 19 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 20 for consideration. There is one amendment (No. 10) by the Minister.

Clause 20 – Declaration of infected areas.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

10. That at page 6, line 19, *for* the words "vernacular language", the words "vernacular language and by declaration in loud voice and by beating drums."; be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 20 as amended was added to the Bill.

Clauses 21 to 24 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 25 for consideration. There is one amendment (No.11) by the Minister.

Clause 25 - Resort to euthanasia for infected animals.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

11. That at page 7, line 22, *for* the words "in the area, he may", the words "in the area or to protect public health if the disease is of zoonotic importance, he may"; be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 25, as amended, was added to the Bill.

Clauses 26 to 30 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 31 for consideration. There is one amendment (No. 12) by the Minister.

Clause 31 - Penalty for issuing vaccination certificate without authority or administering defective vaccine.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

12. That at page 8, line 23, *for* the words "two thousand five hundred rupees", the words "five thousand rupees"; be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 31, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 32 for consideration. There are two amendments (Nos.13 and 14) by the Minister.

Clause 32 - Penalties

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

13. That at page 8, line 29, *for* the words "five hundred rupees", the words "one thousand rupees"; be *substituted*.

14. That at page 8, line 32, *for* the words "one thousand rupees", the words "two thousand rupees"; be *substituted*.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 32, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 33 for consideration. There are two amendments (Nos.15 and 16) by the Minister.

Clause 33 - Penalty for placing infected animal or carcass in river, etc.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

15. That at page 8, line 37, *for* the words "one thousand rupees", the words "two thousand rupees"; be *substituted*.

16. That at page 8, line 39, *for* the words "two thousand rupees", the words "five thousand rupees"; be *substituted*.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 33, as amended, was added to the Bill.

Clause 34 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 35 for consideration. There is one amendment (No.17) by the Minister.

Clause 35 - Prevention of escape of causative organism.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

17 That at page 9, *for* lines 32 and 33, the following be *substituted,* namely, –

"with fine which may extend to twenty thousand rupees or imprisonment for a term which may extend to six months or with both, and in case the establishment is in commercial manufacturing of vaccines or medicine, a temporary suspension of licence up to a period of one year may also be imposed;".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 35, as amended, was added to the Bill.

Clauses 36 to 42 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 43 for consideration. There is one amendment (No. 18) by the Minister.

Clause 43 - Power of State Government to make rules.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

18. That at page 10, line 29, *for* the word "regulations", the word "rules" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 43, as amended, was added to the Bill.

Clauses 44 to 45 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Schedule for consideration. There are four amendments (Nos.19 to 22) by the Minister.

The Schedule

Part I

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

19. That at page 12, *for* lines 1 to 40, the following be *substituted,* namely,

The Schedule

(See sections 2(o) and 38)

(a) Multiple species diseases:-

1. Anthrax.
2. Aujeszky's disease.
3. Bluetongue.
4. Brucellosis.
5. Crimean Congo haemorrhagic fever.

6. Echinococcosis/hydatidosis.

7. Foot and mouth disease.

8. Heartwater.

9. Japanese encephalitis.

10. Leptospirosis.

11. New world screwworm (Cochliomyia hominivorax).

12. Old world screwworm (Chrysomya bezziana).

13. Paratuberculosis.

14. Q fever.

15. Rabies.

16. Rift Valley fever.

17. Rinderpest.

18. Trichinellosis.

19. Tularemia.

20. Vesicular stomatitis.

21. West Nile fever.

(b) Cattle diseases:-

1. Bovine anaplasmosis

2. Bovine babesiosis.

3. Bovine genital campylobacteriosis.

4. Bovine spongiform encephalopathy.

5. Bovine tuberculosis.

6. Bovine viral diarrhoea.

7. Contagious bovine pleuropneumonia.

8. Enzootic bovine leucosis.

9. Haemorrhagic septicaemia.

10. Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis.

11. Lumpy skin disease.

12. Malignant catarrhal fever.

13. Theileriosis.

14. Trichomonosis.

15. Trypanosomosis.";

20. That at page 13, *for* lines 1 to 38, the following be *substituted,* namely,–

"(c) Sheep and goat diseases:-

1. Caprine arthritis/encephalitis.
2. Contagious agalactia.
3. Contagious caprine pleuropneumonia.
4. Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis).
5. Maedi-visna.
6. Nairobi sheep disease.
7. Ovine epididymitis (Brucella ovis).
8. Peste des petits ruminants.
9. Salmonellosis (S. abortusovis).
10. Scrapie.
11. Sheep pox and goat pox.

(d) Equine diseases:-

1. African horse sickness.
2. Contagious equine metritis.
3. Dourine.
4. Equine encephalomyelitis (Eastern).
5. Equine encephalomyelitis (Western).
6. Equine infectious anaemia.
7. Equine Influenza.
8. Equine piroplasmosis.
9. Equine rhinopneumonitis.
10. Equine viral arteritis.
11. Glanders.
12. Surra *(Trypanosoma evansi)*.
13. Venezuelan equine encephalomyelitis.

(e) Swine diseases:-

1. African swine fever.
2. Classical swine fever.
3. Nipah virus encephalitis.
4. Porcine cysticercosis.
5. Porcine reproductive and respiratory syndrome.
6. Swine vesicular disease.
7. Tranmissible gastroenteritis.

(f) Avian diseases:-

1. Avian chlamydiosis.

2. Avian infectious bronchitis.

3. Avian infectious laryngotracheitis.";

21. That at page 14, *for* lines 1 to 35, the following be *substituted,* namely,–

"4. Avian mycoplasmosis *(M. gallisepticum).*

5. Avian mycoplasmosis *(M. synoviae).*

6. Duck virus hepatitis.

7. Fowl Cholera.

8. Fowl typhoid.

9. Highly pathogenic avian influenza and low pathogenic avian influenza in poultry.

10. Infectious bursal disease (Gumboro disease)

11. Marek's disease.

12. Newcastle disease.

13. Pullorum disease.

14. Turkey rhinotracheitis.

(g) Lagomorph diseases:-

1. Myxomatosis.

2. Rabbit haemorrhagic disease.

(h) Bee diseases:-

1. Acarapisosis of honey bees.

2. American foulbrood of honey bees.

3. European foulbrood of honey bees.

4. Small hive beetle infestation Aethina tumida).

5. Tropilaelaps infestation of honey bees.

6. Varroosis of honey bees.

(i) Fish diseases:-

1. Epizootic haematopoietic necrosis.

2. Infectious haematopoietic necrosis.

3. Spring viraemia of carp.

4. Viral haemorrhagic septicaemia.

5. Infectious pancreatic necrosis.

6. Infectious salmon anaemia.

7. Epizootic ulcerative syndrome.

8. Bacterial kidney disease *(Renibactehum salmoninarum)*.

9. Gyrodactylosis *(Gyrodactylus saLaris)*.

10. Red sea bream iridoviral disease.

(j) Mollusc diseases:-

1. Infection with *Bonamia ostreae*.

2. Infection with *Bonamia exitiosa*.";

22. That at page 15, *for* lines 1 to 13, the following be *substituted,* namely, –

"3. Infection with *Marteilia refringens*.

4. Infection with *Mikrocytos mackini*.

5. Infection with *Perkinsus marinus*.

6. Infection with *Perkinsus olseni*.

7. Infection with *Xenohaliotis californiensis*.

(k) Crustacean diseases:-

1. Taura syndrome.

2. White spot disease.

3. Yellowhead disease.

4. Tetrahedral baculovirosis *(Baculovirus penaei)*.

5. Spherical baculovirosis *(Penaeus monodon-type baculovirus)*.

6. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis.

7. Crayfish plague *(Aphanomyces astaci)*.

(l) Other diseases:-

1. Camelpox.

2. Leishmaniosis."

The questions were put and the motions were adopted.

The Schedule, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 1 for consideration. There is one amendment (No.2) by the Minister.

Clause 1 - Short title, extent and commencement.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

2. That at page 2, line 5, *for* the figure "2005", the figure "2008" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Enacting Formulation for consideration. There is one amendment (No.1) by the Minister.

Enacting Formula

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

1. That at page 2, line 1, *for* the word "Fifty-sixth", the word "Fifty-ninth" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

The Gram Nyayalayas Bill, 2008

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Mr. Deputy Chairman, Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the establishment of Gram Nyayalayas at the grass-roots level for the purposes of providing access to justice to the citizens at their doorsteps and to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of social, economic or other disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

Sir, I would like to give a background of this Bill in brief. As you are all aware, this House has discussed, many a times, the question of denial of justice to the poor citizens of this country, particularly to the under-privileged sections, women, children, minorities and others. So, for a long time, this debate has been going on in the country on how to provide speedy, inexpensive and substantial justice to our people. Sir, we have been trying our best to improve the legal system. Yesterday, we debated the problem of arrears. Time and again, discussion has taken place, but, because of financial considerations or cost-effective justice, the States have not been able to cope with the problem of providing speedy and inexpensive justice to our women, children and working classes. Some experiment was made in the State of West Bengal. They brought ADR and conciliation, but because of political reasons there was opposition to it, and they could not enforce it. But the fact remains, in our system this kind of change for disposal of cases is required. We should not bring politics into it We have promised to our people that justice will be speedier and inexpensive. How to do it? So, a joint effort is required at the Central and State levels. I myself went to Kolkata and supported that move despite political opposition. But, unfortunately, we could not provide block level arbitration, conciliation, and mediation. Then I had two meetings with the Law Ministers of the States. In both the meetings, the same demand came that we need money and we need the support of the Centre. They also stated that the Centre must share the responsibility in addition to having fast track courts. The Government of Shri Atal Bihari Vajpayee started fast track courts and the effect was that the number of session trials came down. When we found that they were doing a good work, we